सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

"सब कुछ हर किसी को कहां मिलता है,
किसी को लोग मिलते हैं तो किसी को सुकून...!!"
अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–156 ● संपादक आलोक तिवारी ● दुर्ग, गुरुवार 25 जून 2026 ● पृष्ठ 08 ● मूल्य –2 रुपए

आईएनएस दूनागिरी, अग्रय और संशोधक के लिए 5700 टन रक्षा–ग्रेड स्टील की आपूर्ति

सेल ने दी नौसेना को मजबूती : पीएम मोदी ने 21 जून को तीनों युद्धपोतों को नौसेना में किया शामिल

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। सेल ने हाल ही में कमीशन किए गए तीन अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक के निर्माण के लिए पूरे 5,700 टन विशेष रक्षा–ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है।

पीएम ने किया कमीशन

तीनों उन्नत जहाजों को 21 जून, 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया। आईएनएस दूनागिरी एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है। आईएनएस अग्रय एंटी–सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट है। आईएनएस संशोधक एक सर्वेक्षण पोत है।

भिलाई, बोकारो, राउरकेला से हुई आपूर्ति

सेल ने इन तीनों जहाजों के लिए विशेष गुणवत्ता की ऊटफ 249अ ग्रेड हॉट–रोल्ड शीट और प्लेट की आपूर्ति की है। कंपनी ने इस डिफेंस ग्रेड स्टील का उत्पादन अपने बोकारो, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों से किया है। सेल का

कहना है कि यह उत्पादन देश की समुद्री सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने की आधुनिक तकनीकी क्षमता का प्रमाण है।

आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा

सेल 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियानों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। कंपनी ने रक्षा क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए डीएमआर ग्रेड प्लेटों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राउरकेला स्टील प्लांट के स्पेशल प्लेट प्लांट में अतिरिक्त पहल की है। यह कदम रक्षा–ग्रेड स्टील के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम कर रहा है।

पहले भी की है आपूर्ति

सेल पहले भी स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत के साथ प्रोजेक्ट 17अ स्टील्थ फ्रिगेट्स आईएनएस नीलगिरि, आईएनएस हिमगिरि और आईएनएस उदयगिरि के लिए स्टील की आपूर्ति कर चुका है। इसके अलावा आईएनएस अजय, आईएनएस निस्तार और आईएनएस अंजदीप में भी सेल का विशेष स्टील इस्तेमाल हुआ है।

सीएमडी बोले, रक्षा क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध

सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अशोक कुमार पंडा ने कहा कि सेल देश की आत्मनिर्भरता की जरूरतों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कंपनी ने डीएमआर ग्रेड प्लेटों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। DMR 249अ स्टील प्लेटों की आपूर्ति भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूती देती है और सेल की तकनीकी विशेषज्ञता को भी प्रमाणित करती है।

राजनांदगांव में 76 करोड़ का फर्जी बिल खेल, संचालक सलाखों के पीछे

स्टेट जीएसटी का बड़ा वार : 8 .22 करोड़ की फर्जी ITC का पर्दाफाश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर–राजनांदगांव

कर चोरों पर स्टेट जीएसटी की गाज गिरी है। राजनांदगांव में 76 करोड़ रुपये की फर्जी बिल ट्रेडिंग का भंडाफोड़ हुआ है। मैसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया है।

6 महीने में 76 करोड़ का कागजी खेल

जांच में खुलासा हुआ कि फर्म ने छह महीने में 76 करोड़ का लेन–देन सिर्फ कागजों पर दिखाया। दस्तावेजों की छानबीन में 8.22 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी निकली। सरकार को करोड़ों की चपत लगाने का पूरा प्लान था।

बंगाल से आया फर्जी बिल का जखीरा

फर्म ने पश्चिम बंगाल की संदिग्ध फर्मों से आयरन और स्टील की खरीदी दिखाई। हकीकत में एक किलो माल नहीं आया, लेकिन करोड़ों के बिल जरूर बन गए। उन्हीं बिलों के दम पर फर्जी क्ळठ हड़पी और दूसरे करदाताओं को भी बांट दी।

जांच में निकलीं घोस्ट कंपनियां

जिन फर्मों से खरीदी बताई गई, उनके जीएसटी नंबर पहले ही रद्द हो चुके हैं। न दफ्तर मिला, न गोदाम। पूरा रैकेट सिर्फ पेपर ट्रेडिंग और बोगस क्ळठ के लिए चल रहा था। माल का आवागमन जीरो, सिर्फ बिलों से टैक्स की लूट।

नेटवर्क में कई और चेहरे

स्टेट जीएसटी ने आदेश्वर चौरड़िया को दबोच लिया है। जांच अभी जारी है। बैंक खाते, ई–वे बिल और परिवहन दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में कई और फर्मों और लोगों के इस जाल में फंसे होने के संकेत मिले हैं। विभाग ने दो टूक कहा है कि ईमानदार करदाताओं की रक्षा होगी और फर्जी बिल माफियाओं पर इसी तेवर से कारर्वाई जारी रहेगी।

भिलाई नगर निगम में टकराव : दो महीने से एमआईसी–सामान्य सभा हुई ठप्प

32 काम नोटिस बोर्ड पर चिपके, महापौर–आयुक्त की खींचतान में विकास अटका, पार्षदों में बेचैनी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई नगर निगम में महापौर नीरज पाल और आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के बीच चल रही खींचतान से शहर का विकास थम गया है। दो महीने से न एमआईसी की बैठक हो रही है, न सामान्य सभा की तारीख तय हुई। नतीजाः 32 से अधिक जरूरी काम नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर रख दिए गए हैं।

बैठकें लगातार स्थगित

आखिरी बार 29 अप्रैल को एमआईसी बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन महापौर ने आयुक्त के खिलाफ न्यायालय में लंबित याचिका का हवाला देकर स्थगित कर दी। 8 मई को फिर कोशिश हुई पर टकराव के चलते बैठक नहीं हो पाई। आयुक्त ने 11 मई से 15 जून तक दर्जनभर बार एजेंडा जारी किया, लेकिन हर बार बैठक टल गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षद अब आयुक्त को मानने को तैयार नहीं हैं।

'चुनाव क्यों करवाएं'

महापौर नीरज पाल ने कहा कि भाजपा पार्षद के प्रस्ताव पर सामान्य सभा सर्वसम्मति से आयुक्त को हटाने का निर्णय ले चुकी है। आयुक्त सामान्य सभा न मानते हुए अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहाः "यदि आयुक्त ही शहर सरकार चलाएंगे तो निगम के चुनाव भी मत करवाओ।"

'10 दिन में काम स्वत : पास'

आयुक्त राजीव पाण्डेय का तर्क है कि यदि 10 दिन तक एमआईसी प्रस्ताव पास नहीं करती तो काम स्वतः पास माने जाते हैं। इसी वजह से नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। उन्होंने कहा कि तीन करोड़ से ऊपर के काम सामान्य सभा में जाते हैं। बैठक न होने से काम अटके हैं। महापौर से चैंबर मांगा लेकिन नहीं दिया गया।

पार्षद परेशान : चुनाव सिर पर

छह महीने में निगम चुनाव हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद बेचैन हैं। सड़क, सफाई जैसी बुनियादी समस्याएं जस की तस हैं। टेंडर और स्वीकृति अटके हैं। वार्डों में विरोध झेल रहे पाषर्दों का कहना है कि विकास कार्य नहीं हुए तो जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे।

शासन–प्रशासन मौन

सूत्रों के अनुसार आयुक्त ने ई–ऑफिस के जरिए संभाग आयुक्त को जानकारी दी है और बैठक सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। महापौर कलेक्टर और शासन स्तर पर शिकायत कर चुके हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि सूचना शासन को दे दी है। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने कहा कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है।

फिलहाल भिलाई और दुर्ग दोनों निगमों में शीर्ष पदों के टकराव से विकास ठप है। शासन–प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं दिख रही।

छग में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव, सीएम साय ने अमित शाह से की मुलाकात

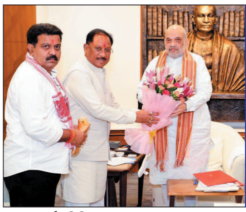

बोले, औषधीय संपदा से समृद्ध है प्रदेश, AIIA से मिलेगा मध्य भारत को लाभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का आग्रह किया। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे।

आयुर्वेद का राष्ट्रीय केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को आयुर्वेद चिकित्सा, अनुसंधान और उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली और पणजी में संचालित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान देश में आयुर्वेद आधारित चिकित्सा और नवाचार के उत्कृष्ट केंद्र बन चुके हैं।

औषधीय वनस्पतियों से समृद्ध प्रदेश : मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों और औषधीय संपदा से समृद्ध है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा वनाच्छादित है जहां दुर्लभ औषधीय वनस्पतियां और जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। जनजातीय अंचलों में पारंपरिक औषधीय ज्ञान की समृद्ध विरासत भी है। यहां अक्क्अ की स्थापना से आयुर्वेद चिकित्सा और अनुसंधान को नई ऊंचाई मिलेगी।

युवाओं को मिलेंगे अवसर : उन्होंने कहा कि संस्थान की स्थापना से प्रदेशवासियों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अध्ययन और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। इससे आयुर्वेद आधारित चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

मध्य भारत को होगा फायदा : मुख्यमंत्री ने बताया कि संस्थान का लाभ केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य भारत के व्यापक क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों के नागरिकों को भी बेहतर आयुर्वेदिक उपचार और शोध सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

बजट में तीन नए संस्थानों की घोषणा : श्री साय ने केंद्रीय बजट 2026 में देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा का उल्लेख किया। उन्होंने आग्रह किया कि इनमें से एक संस्थान छत्तीसगढ़ को दिया जाए। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रोजगार और अनुसंधान को भी गति मिलेगी।

केंद्र ने दिया सहयोग का आश्वासन : बैठक में मुख्यमंत्री ने बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के विकास प्रयासों की सराहना की और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला, देश कभी नहीं भूलेगा वह काला दौर : जयंती पटेल

51वीं वर्षगांठ पर भाजपा की प्रेस वार्ता, कांग्रेस पर साधा निशाना; लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का लिया संकल्प

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

भारतीय जनता पार्टी ने देश में लगाए गए आपातकाल की 51वीं वषर्गांठ के अवसर पर बुधवार को बेमेतरा में प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि यह वह दौर था, जब संविधान की मूल भावना, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया था।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री जयंती भाई पटेल ने कहा कि 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति का हवाला देकर देश में आपातकाल लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था को गंभीर आघात पहुंचा। उन्होंने कहा कि उस समय विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र समर्थक आवाजों को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। हजारों लोगों को बिना सुनवाई जेलों में बंद कर दिया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए।

उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप लागू कर समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों की आवाज को नियंत्रित किया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित हुई और शासन व्यवस्था में भय एवं दमन का वातावरण पैदा कर दिया गया। श्री पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र ने उस कठिन दौर को झेला, लेकिन देश की जनता और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों के संघर्ष के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित हुई।

नई पीढ़ी को इतिहास जानना जरूरी

भाजपा प्रदेश मंत्री श्री पटेल ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल के इतिहास और उससे जुड़े घटनाक्रम की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है ।उन्होंने कहा कि आपातकाल की घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर सजग रहना आवश्यक है। यदि लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी की जाती है, तो नागरिक अधिकारों और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर संकट उत्पन्न हो सकता है।

कांग्रेस पर लगाए लोकतांत्रिक परंपराएं कमजोर करने के आरोप

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 25 जून का दिन देश के इतिहास में लोकतंत्र पर कुठाराघात के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लिए गए फैसले भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि देश की जनता को उस दौर की घटनाओं को स्मरण रखना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधान और नागरिक अधिकारों पर संकट उत्पन्न न हो।

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का दोहराया संकल्प

आपातकाल की 51वीं वषर्गांठ पर भाजपा ने लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए कार्य करती रहेगी। प्रेसवार्ता में प्रहलाद रजक (रजक बोर्ड अध्यक्ष), विजय सिन्हा (नगर पालिका अध्यक्ष), मीडिया प्रभारी दीपक मोटवानी ,हर्षवर्धन तिवारी,विनय साहू , शहर भाजयुमो अध्यक्ष हेतुल्य सिंह सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

महिला एवं बाल विकास दफ्तर के सामने का

दुर्लभ नजारा : धमतरी कलेक्ट्रेट में सांपों के जोड़े की अठखेलियां

नई दृष्टिबिंदु / धमतरी

कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को उस समय हलचल मच गई जब महिला एवं बाल विकास कार्यालय के सामने दो सांप आपस में लिपटकर अठखेलियां करते नजर आए। दफ्तरी काम छोड़कर कर्मचारी और लोग यह अनोखा नजारा देखने जुट गए।

कर्मचारियों ने बनाया वीडियो

सांपों के जोड़े को काफी देर तक एक–दूसरे के साथ घूमते और प्राकृतिक गतिविधियां करते देख कमर्चारियों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे प्रकृति का दुर्लभ दृश्य बता रहे हैं।

मानसून ने बढ़ाई हलचल

जानकारों का कहना है कि मानसून में सांप ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। बारिश के साथ हरियाली वाले इलाकों और खुले स्थानों में इनका दिखना आम हो जाता है। कलेक्ट्रेट में दिखा यह नजारा भी मानसून की आहट से जोड़कर देखा जा रहा है।

घंटो देखते रह गए लोग

कुछ देर तक कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोग सांपों की गतिविधियां देखते रहे। कई लोगों ने इसे अद्भुत और दुर्लभ पल बताया। कोई डरा नहीं, बल्कि सबने कैमरे में इस नजारे को कैद कर लिया।

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

घटना का वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर तेजी से शेयर हो रहा है। लोग इसे वन्यजीवों के व्यवहार और प्रकृति की खूबसूरती का अनोखा उदाहरण बता रहे हैं।

'आरंभ' के आयोजनों में सर्वधर्म समभाव एवं परस्पर सामाजिक सद्भाव का वातावरण : डॉ. महेश चंद्र शर्मा

'आरंभ' बना हर मौन कलम को आवाज देने का मंच : डॉ. चक्रवर्ती, साहित्य को उन्नति के सवोच्च शिखर पर रखने का कार्य कर रहे 'आरंभ' के साहित्यकार : साटकर

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

प्रगतिशील जन-विचारधारा की साहित्यिक संस्था 'आरंभ' द्वारा आयोजित सातवीं सांगठनिक बैठक भिलाई निवास के इंडियन कॉफी हाउस सभागार में सम्पन्न हुई। मुख्य अतिथि एवं मोटिवेशनल स्पीकर 'स्वयंसिद्धा' की अध्यक्ष डॉ सोनाली चक्रवर्ती थी। अध्यक्षता संस्था के मुख्य सलाहकार आचार्य डॉ महेश चंद्र शर्मा ने की। सांगठनिक बैठक की अध्यक्षता 'आरंभ' के मुख्य संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा ने की। विशिष्ट अतिथि संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रयम्बक राव साटकर 'अंबर', उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नीलम चंद सांखला और सेवानिवृत्त उप वन मंडल के अधिकारी अब्दुल वहीद खान थे।

सरस्वती वंदना गीत की प्रस्तुति संध्या साटकर ने की। आयोजकीय वक्तत्व ठाकुर दशरथ सिंह भुवाल सोनपांडर और स्वागत उद्बोधन 'आरंभ' के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य एवं आभार व्यक्त ब्रजेश मल्लिक ने दिया। प्रतिवेदन एवं संस्था का उद्देश्य मुख्य संचालिका संस्था की महासचिव नुरू सबाह खान 'सबा' और काव्य पाठ का संचालन उपाध्यक्ष दीप्ति श्रीवास्तव ने किया।

इस दौरान जानकारी दी गई कि संस्था का राज्य स्तरीय पंजीयन 25 मई को होने के बाद से अब सदस्य संख्या 51 हो गई है। सांगठनिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैलाश जैन बरमेचा ने सभी सदस्यों का आत्मीय स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। डॉ सोनाली चक्रवर्ती ने कहा कि- हर मौन कलम को आवाज देने का मंच है, शोषितों के स्वरों का यह प्रखर उद्घोष-स्तम्भ है, एक नई सोच का नाम 'आरंभ' है। आचार्य डॉ महेशचंद्र शर्मा ने कहा कि- साहित्य की विविध विधाओं को समर्पित 'आरंभ' के आयोजनों में सर्वधर्म समभाव एवं परस्पर सामाजिक सद्भाव का वातावरण देखते ही बनता है। त्रयम्बक राव साटकर 'अंबर' ने कहा कि

साहित्य को उन्नति के सवोच्च शिखर पर देखना एक कवि अथवा साहित्यकार का प्रथम लक्ष्य होता है। यही कार्य हमारे 'आरंभ' के साहित्यकार कर रहे हैं

इस अवसर पर नीलम चंद सांखला और अब्दुल वहीद खान ने भी अपने विचार प्रकट किए। दूसरे सत्र में काव्य पाठ हुआ। सभी रचनाकारों को 'आरंभ' प्रतिभागी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। काव्य पाठ करने वालों में प्रमुख रूप से डॉ संध्या श्रीवास्तव, वर्षा ठाकुर, गजेंद्र द्विवेदी 'गिरीश', तारकनाथ चौधुरी, अमृता मिश्रा, डॉ विजय कुमार गुप्ता 'मुन्ना', शशिप्रभा गुप्ता, नुरू सबाह खान 'सबा', नीलम चंद सांखला, प्रकाश चंद्र मण्डल, राकेश गुप्ता 'रुसिया', जाविद हसन 'भाईजान', डॉ दीक्षा चौबे, मिताली श्रीवास्तव वर्मा, फरीदा शाहीन अंसारी, सुशील यादव, शौकत इकबाल, नितिन गोस्वामी, पल्लव चटर्जी, माला सिंह, राजकुमार भल्ला 'आर्य', शिवचरण दास गोयल, कमलेश तिवारी, प्रदीप कुमार पाण्डेय, डॉ नौशाद अहमद सिद्दीकी 'सब्र', ठाकुर दशरथ सिंह भुवाल सोनपांडर, अब्दुल वाहिद खान और ब्रजेश मल्लिक शामिल थे।

इस अवसर पर डॉ सोनाली चक्रवर्ती को 'आरंभ' मोमेंटों,शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में शेफाली भट्टाचार्य, संध्या साटकर, शानू मोहनन, अनिल खरे, आलोक चौधुरी, अपिर्ता चौधुरी, महेश तिवारी, दीपमाला सिन्हा, शेखर साहू और अनेक बुद्धिजीवी एवं 'आरंभ' के सदस्यगण उपस्थित रहे। ये जानकारी 'आरंभ' के प्रवक्ता जाविद हसन 'भाईजान' ने दी।

खास खबर

भाजपा सरकार पर अरूण वोरा ने साधा निशाना, गरीबों की शक्कर गायब, ई-केवाईसी भी लंबित

नई दृष्टिबिंदु /दुर्ग

एक तरफ भाजपा सरकार गरीब कल्याण के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ लाखों गरीब परिवार पिछले तीन महीनों से राशन दुकानों में मिलने वाली शक्कर के लिए भटक रहे हैं। वहीं जिले में राशनकार्डों में दर्ज 1 लाख 33 हजार 14 सदस्यों की ई-केवाईसी अब तक लंबित है। शासन ने 15 जुलाई तक इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो हजारों परिवार राशन व्यवस्था से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। इन गंभीर अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व विधायक अरुण वोरा एवं पूर्व महापौर आरएन वर्मा खाद्य विभाग पहुंचे और अधिकारियों से जवाब तलब किया।

अरुण वोरा ने कहा कि सरकार और खाद्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा सीधे गरीब और जरूरतमंद परिवार भुगत रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है, जिन परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी चुनौती है, उन्हें राशन की मूलभूत सामग्री के लिए भटकाया जा रहा है। तीन-तीन महीने तक शक्कर का वितरण नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है।जिन परिवारों की रसोई पहले ही महंगाई की मार से जूझ रही है, उनसे शक्कर जैसी आवश्यक वस्तु भी छीन ली गई है। वोरा ने सवाल उठाया कि जब शक्कर वितरण महीनों से प्रभावित है तो क्या सरकार और विभाग के अधिकारी केवल कागजों में योजनाएं चलाने तक सीमित हैं?

उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के नाम पर भी गरीबों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।लाखों लोगों की प्रक्रिया लंबित है,प्रक्रिया भी बेहद धीमी गति से चल रही है,समयसीमा नजदीक है, लेकिन विभाग ने जागरूकता और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। यदि समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गईं तो हजारों पात्र परिवार राशन प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करेंगे।इसका खामियाजा अंततः गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के "सुशासन" की सच्चाई अब राशन दुकानों की कतारों में खड़े गरीबों पर साफ दिखाई दे रही है। सरकार के विज्ञापनों में विकास दिख सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गरीब आज भी अपने हक के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।वोरा ने अधिकारियों से लंबित शक्कर का तत्काल वितरण सुनिश्चित करने, ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने तथा हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गरीबों के हक़ पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस जनता की आवाज बनकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।

पूर्व महापौर आर एन वर्मा ने कहा कि- गरीबों के अधिकारों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। खाद्य विभाग को तत्काल लंबित शक्कर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना चाहिए, ताकि किसी भी हितग्राही को उसके अधिकार से वंचित न होना पड़े।

जिले में भीम का मैंगो आइस कैंडी के विक्रय पर प्रतिबंध

दुर्ग। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने भीम का मैंगो (पैक्ड) ग्रीन कलर (मैंगो आईस कैंडी) के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देश पर की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त उत्पाद का नमूना मानकता जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन में संबंधित उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनियम 2011 के तहत उक्त खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ के उक्त बैच नम्बर के विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी कैंडी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे उक्त उत्पाद का विक्रय न करें।

डायल 112 कर्मचारियों व चालकों की बैठक उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान

पुलिस अधीक्षक ने त्वरित और संवेदनशील पुलिस सहायता सुनिश्चित करने दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु /दुर्ग

जिला दुर्ग में डायल 112 सेवा को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से 24 जून 2026 को डायल 112 में पदस्थ कर्मचारियों एवं चालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कर्मचारियों को त्वरित, प्रभावी एवं संवेदनशील कार्यवाही सुनिश्चित करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान ग्रामीण एवं शहरी थाना क्षेत्रों में संचालित ईआरयू वाहनों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त इवेंटों पर निर्धारित समय में घटनास्थल पहुंचकर पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही आम नागरिकों के प्रति शालीन व्यवहार, आपात परिस्थितियों में बेहतर समन्वय एवं जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य निर्वहन पर विशेष जोर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि डायल 112 पुलिस और आमजन के बीच त्वरित सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक कमर्चारी एवं चालक को संवेदनशीलता, अनुशासन एवं तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बैठक के दौरान सी-4 रायपुर से प्राप्त इवेंटों में उत्कृष्ट कार्य कर समय पर सहायता पहुंचाने वाले डायल 112 के स्टार कर्मचारियों एवं चालकों को उत्साहवर्धन के लिए कैश रिवार्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

सम्मानित कर्मचारियों में प्रधान आरक्षक भगतराम चंद्रवंशी, आरक्षक राजेश कुमार पाल, कौशलेंद्र सिंह, योगेंद्र बिलोने, शकील खान, गौतम भट्ट, बी. लक्ष्मण राव, सुमन मंडावी, हेमेन्द्र बंछोर, त्रिलोचन ठाकुर, फल्गो वर्मा एवं यशवंत देशमुख शामिल रहे। इसी प्रकार चालक संतोष कुमार, गोविंदा सिंह, तोपेश सोनवानी, बग्गा सिंह, लोकेश कुमार, डेविड ठाकुर, अश्वनी कुमार, सुनील कुमार, विनोद कुमार, सुनील देशमुख, भीषम साहू, हेमंत कुमार, मनोज चंद्राकर, दिलेश्वर साहू, प्रीतम जांगड़े, थानेश्वर साहू, झानेश्वर एवं चित्रसेन को भी सम्मानित किया गया। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल डायल 112 सेवा का उपयोग करें तथा समय पर सही जानकारी देकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर याद किए गए उनके शौर्य और साहस

नई दृष्टिबिंदु /दुर्ग

वीरांगना रानी दुर्गावती के 462वें बलिदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ द्वारा सिविल लाइन चौक स्थित साईं द्वार के सामने स्थापित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने प्रतिमा का पूजन कर माल्यार्पण किया तथा उनके अद्वितीय शौर्य, साहस और बलिदान को नमन किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अरुण वोरा शामिल हुए। वहीं केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के अध्यक्ष एमडी ठाकुर, कोषाध्यक्ष सीताराम ठाकुर, दुष्यंत शोरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में दिलीप ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अरुण वोरा ने रानी दुर्गावती के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन कभी भी शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके। उनके साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना आज भी समाज को प्रेरित करती है। केन्द्रीय गोंडवाना महासभा धमधागढ़ के अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि रानी दुर्गावती का जीवन संघर्ष, त्याग और वीरता का अनुपम उदाहरण है।

कार्यक्रम के दौरान रानी दुर्गावती अमर रहें और शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती अमर रहें के नारों से वातावरण गूंज उठा। महिला मित्र गोंडवाना संगठन की सदस्यों ने भी रानी दुर्गावती के शौर्य, वीरता और बलिदान से जुड़े प्रेरक संस्मरण साझा किए तथा उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। शहादत दिवस कार्यक्रम में समाज के करण नेताम, पन्ना नेताम, कमलेश नागरची, भीष्म नागेश माहेश्वरी, कोयल, चंद्रकांता, शरद, राजेश्वरी, पूजा, सेवती, भानुप्रभा नेताम, ऊषा, चंद्रकला, अनीता नेताम, पूणिर्मा, प्रभा, पूनम, राहुल, रमेश साहू सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।

युवाओं को भी जानना चाहिए कि इमरजेंसी में देश की जनता ने कितनी यातनाएं झेली- सोनी

नई दृष्टिबिंदु /दुर्ग-भिलाई

आपातकाल की 51वीं बरसी के पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे अलोकतांत्रिक काल बताते हुए कहा कि देश के युवाओं को भी यह जानना चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान नागरिक अधिकारों पर किस प्रकार प्रतिबंध लगाए गए और जनता को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल लागू रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। इस दौरान

आपातकाल की 51वीं बरसी से पूर्व भाजपा की प्रेस वार्ता आयोजित

चुनाव स्थगित किए गए तथा नागरिक अधिकारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए। विधायक सोनी ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस अवधि को भारतीय इतिहास का सबसे कठिन लोकतांत्रिक दौर बताया था। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार के खिलाफ देशभर में असंतोष का माहौल था और न्यायालय के निर्णय के बाद राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आपातकाल लागू किया गया। उनके अनुसार आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अनेक संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा व्यापक स्तर पर आंदोलन हुए।

विधायक सुनील सोनी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत हैं तथा इन्हें सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आपातकाल के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए इतिहास से सीख लेना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हों। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री विनोद अरोरा, जिला उपाध्यक्ष मनोज सोनी, प्रवक्ता रजा खोखर, मीडिया प्रभारी राजा महोबिया, वरिष्ठ भाजपा नेता अजय तिवारी एवं विनायक नातू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना : 15 हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से मिला अपने घर का सपना

महापौर ने सौंपे आवंटन पत्र, किराये पर देने पर कार्रवाई की दी चेतावनी

नई दृष्टिबिंदु /दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एएचपी घटक में निर्मित आवासों के आवंटन की प्रक्रिया लगातार जारी है। सरस्वती नगर, मां कर्मा बोरसी एवं गोकुल नगर में बनाए गए किफायती एवं आकर्षक आवासों के लिए नागरिकों में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

निगम प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त आवेदनों के आधार पर पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस माह गोकुल नगर के 1, सरस्वती नगर के 9 तथा मां कर्मा बोरसी के 5 आवासों सहित कुल 15 आवेदनों पर लॉटरी निकालकर हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए।

आवंटन प्रक्रिया महापौर श्रीमती अलका बाघमार की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस दौरान

एमआईसी सदस्य देव नारायण चंद्राकर, पार्षद सरिता चंद्राकर एवं कार्यपालन अभियंता सुश्री विनिता वर्मा भी मौजूद रहीं। लॉटरी प्रक्रिया में हितग्राहियों ने स्वयं पर्ची निकालकर अपने आवास का चयन किया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

महापौर ने चयनित हितग्राहियों को आवंटन पत्र प्रदान करते हुए उन्हें बधाई दी। निगम प्रशासन ने जानकारी दी कि आवास की सम्पूर्ण राशि जमा करने के बाद हितग्राहियों को आधिपत्य पत्र प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकानों में केवल पात्र हितग्राही ही निवास करेंगे। यदि कोई हितग्राही आवास को किराये पर देता पाया गया तो निगम प्रशासन द्वारा आवंटन निरस्त करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में दीपक संचेती, टिकेश्वर दास साहू (सीएलटीसी), रामदास साहू सहायक ग्रेड-03 सहित निगम के अधिकारी एवं कमर्चारी उपस्थित रहे।

वार्ड नं. 48 स्थित सार्वजनिक शौचालय जल्द शुरू होगा

वार्ड नंबर 48 न्यू पुलिस लाईन के पास नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय जिसमें पौने दो सालों से ताला लटका हुआ था वह जल्द खुलेगा। तीन चार दिनों के भीतर ही उसके बचे काम को पूरा कराकर उसका लोकार्पण हो जाएगा। यह आश्वासन नगर निगम के आयुक्त ने कांग्रेस के पूर्व पार्षदों के प्रतिनिधिमण्डल को दिया है। जिन्होने उत्कल नगर के लोगों की समस्या को लेकर उन्हें आज एक ज्ञापन सौंपा। आयुक्त ने बताया कि उक्त शौचालय सुविधा 24 योजना के तहत बना है। यह योजना सरकार ने बंद कर दी थी। इसलिए कोई भी संस्था उसके संचालन के लिए तैयार नहीं हो रही थी लेकिन अब एक एजेंसी संचालन के लिए राजी हो गया है। तीन चार दिनों में उसका शेष कार्य पूरा कर उसे प्रारंभ करा दिया जाएगा। शीतला स्वरूपा मंदिर प्रांगण में तात्कालीन महापौर धीरज लाल बाकलीवाल की महापौर निधि से बनवाए गए जिम से सामान गायब होने के मामले की भी जांच कराने का आयुक्त ने आश्वासन दिया। कलेक्टर एसपी बंगले के सामने सड़क किनारे बनाए जा रहे पेवर ब्लॉक के निर्माण में गड़बड़ी के बारे में भी आयुक्त ने कहा कि उसका निर्माण सही तरीके से कराया जाएगा ताकि बारिश का पानी जमीन के अंदर जाए और भूजल स्तर बढ़े। ठगड़ा बांध के पास जल भराव की समस्या पर उन्होंने कहा कि यह सिंचाई विभाग का मामला है। इस बारे में उनसे चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में नगर निगम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अब्दुल गनी, देवकुमार जंघेल, लिखन साहू, वार्ड क्रमांक 48 पूर्व पार्षद महेश्वरी ठाकुर, पूर्व पार्षद अमृत लोढ़ा, संजय सिंह, भोला महोबिया, मनोज चंद्राकर, मनीष यादव, राजकुमार वर्मा, आदि शामिल थे।

स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार, महारानी अस्पताल के कायाकल्प के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव

मॉड्यूलर ओटी, पीडियाट्रिक आईसीयू और सोलर सिस्टम से लैस होगा अस्पताल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-जगदलपुर

बस्तर संभाग के लाखों लोगों को जल्द ही स्थानीय स्तर पर सुपर-स्पेशलिटी स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जगदलपुर के ऐतिहासिक महारानी अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा केंद्र बनाने के लिए 7 करोड़ 1 लाख रुपये से अधिक का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अस्पताल का कायाकल्प दो से अधिक चरणों में किया जाएगा।

जीवन दीप समिति की बैठक में लिए गए फैसले

कलेक्टर आकाश छिकारा की अध्यक्षता में हुई जीवन दीप समिति की बैठक में अस्पताल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। ओपीडी, आपातकालीन इकाई, ओटी कॉम्प्लेक्स और आईसीयू का उन्नयन किया जाएगा।

आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और नई मशीनें

प्रसूति, स्त्री रोग और सामान्य सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटरों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सीटी स्कैन के लिए विद्युत व्यवस्था सुधारी जाएगी। कलर डॉपलर, मोबाइल डीआर सिस्टम, एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी जैसी नई मशीनें खरीदी जाएंगी। नेत्र और ईएनटी उपचार के लिए आधुनिक उपकरण मंगाए जाएंगे।

शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर

12 बिस्तरीय पीडियाट्रिक आईसीयू और 30 बिस्तरीय शिशु रोग वार्ड के संचालन के लिए मरम्मत व सुरक्षा कार्यों को मंजूरी दी गई है। रठउव और टठउव वार्डों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीदी होगी।

सोलर सिस्टम से बनेगा आत्मनिर्भर

निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 78 लाख रुपये की लागत से ऑन-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम लगेगा। 65 लाख रुपये की लागत से नया डीजी

सेट भी लगाया जाएगा। मरीजों के परिजनों के लिए पार्किंग सुविधा और होम शेल्टर का निर्माण होगा।

धन्वंतरी दवा केंद्र का अनुबंध नहीं बढ़ेगा

पारदशिर्ता के लिए समिति ने धन्वंतरी दवा केंद्र के वतर्मान अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाने की सिफारिश की है। अटल आरोग्य लैब के तहत माइक्रोबायोलॉजी विभाग जल्द शुरू होगा। बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और एयर हैंडलिंग यूनिटों की मरम्मत को भी मंजूरी मिली है।

समय पर पूरे होंगे काम

कलेक्टर आकाश छिकारा ने निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य समय-सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले गरीब मरीजों को जगदलपुर में ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा देना है ताकि उन्हें बाहर न भटकना पड़े।

खास खबर

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी के लिए अब सीधे खाते में मिलेंगे पैसे

केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था खत्म, पसंद की साड़ी चुन सकेंगी बहनें

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महिला एवं बाल विकास विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था खत्म कर दी है। अब साड़ी की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि हाल में साड़ी खरीदी को लेकर मिले सुझावों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और कार्यकर्ताओं को अपनी पसंद की साड़ी चुनने की आजादी मिलेगी।

DBT से होगा भुगतान : मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप शासन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे हितग्राही तक पहुंचाई जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन का यह नया मॉडल है।

डिजाइन वेबसाइट पर, कपड़ा चुनने की छूट : साड़ी का डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा। अंतिम स्वरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परामर्श के बाद तय होगा। साड़ी का रंग और डिजाइन विभाग की वेबसाइट पर डाला जाएगा ताकि एकरूपता बनी रहे। कपड़ा कॉटन, सिंथेटिक या अन्य विकल्प स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता खुद चुन सकेंगी।

500 रुपये प्रति यूनिफॉर्म तय : भारत सरकार की बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को हर साल दो यूनिफॉर्म दी जाती हैं। इसके लिए प्रति यूनिफॉर्म अधिकतम 500 रुपये की राशि तय है। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि विभाग आंगनबाड़ी बहनों के सम्मान और सुविधा के प्रति संवेदनशील है। जहां भी सुधार की जरूरत होगी, हितग्राहियों के हित में बदलाव किए जाएंगे। यह फैसला पारदर्शी प्रशासन की दिशा में अहम कदम है।

कांकेर और जशपुर में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

खाद्य विभाग की अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें, कृषि कार्यों के लिए बढ़ाई गई आपूर्ति

रायपुर। राज्य सरकार प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि कांकेर और जशपुर जिले में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति सामान्य है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

कांकेर में 51 पेट्रोल पंप संचालित : कांकेर जिले में कुल 51 पेट्रोल पंप संचालित हैं। इनमें इंडियन ऑयल के 14, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के 21 और भारत पेट्रोलियम के 16 पंप शामिल हैं। प्री-मानसून वर्षा के बाद खरीफ फसल की तैयारियों के चलते कृषि कार्यों के लिए डीजल की मांग बढ़ी है। 23 जून को कोयलीबेड़ा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप में डीजल का स्टॉक खत्म होने से अस्थायी स्थिति बनी थी। किसानों की सुविधा के लिए निकटवर्ती पंपों से डीजल उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल की गई। वतर्मान में कोयलीबेड़ा क्षेत्र के दोनों पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। ईंधन वितरण सुचारु रूप से चल रहा है।

जशपुर में 61 पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सुचारु : जशपुर जिले में कुल 61 पेट्रोल पंप संचालित हैं। इनमें इंडियन ऑयल के 28, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के 24 और भारत पेट्रोलियम के 9 पंप शामिल हैं। 23 जून को कोतबा क्षेत्र के दो पेट्रोल पंपों में डीजल स्टॉक खत्म होने से अस्थायी स्थिति बनी थी। निकटवर्ती पंपों से वैकल्पिक आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की गई। वर्तमान में कोतबा क्षेत्र के सभी चार पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। ईंधन वितरण नियमित रूप से हो रहा है।

तेल कंपनियों को दिए निर्देश : जिला और राज्य स्तर पर तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि कार्यों के कारण जिन पेट्रोल पंपों में स्टॉक खत्म होने की संभावना है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त आपूर्ति देने के लिए तेल कंपनियों को निर्देशित किया गया है। खाद्य विभाग ने कहा कि दोनों जिलों में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। आम नागरिकों और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

भारतमाला परियोजना के निर्माणाधीन दो राष्ट्रीय राजमार्ग मार्च 2027 तक होंगे पूरे

पीडब्ल्यूडी सचिव ने की समीक्षा, ठेकेदारों को बरसात में वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन रायपुर-विशाखापटनम एक्सप्रेस-वे और दुर्ग-आरंग बायपास का काम मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने मंगलवार को अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की समीक्षा की।

बरसात में न हो परेशानी

सचिव बंसल ने पेंशनबाड़ा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालय में हुई बैठक में ठेकेदारों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन सड़कों पर वैकल्पिक या डायवर्टेड मार्ग बनाकर काम करें। इससे बरसात में लोगों को आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने केशकाल घाटी बायपास में सड़क के साथ ही दो बड़े पुलों का काम भी जल्द शुरू करने को कहा।

इकोनॉमिक कॉरीडोर से जोड़ने के प्रस्ताव

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरीडोर का काम भी तेज गति से चल रहा है। सचिव बंसल ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली भारतमाला परियोजना की सड़कों का पूरा लाभ उठाने के लिए राज्य की सड़कों को इनसे जोड़ने टू-लेन और फोर-लेन सड़कों के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सड़क खंडों के चालू होने से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।

रायपुर में तीन फ्लाईओवर प्रस्तावित

बैठक में एनएचएआई द्वारा रायपुर के तेलीबांधा चौक, उद्योग भवन चौक और सरोना चौक में प्रस्तावित फ्लाईओवर्स की स्वीकृति की प्रगति पर भी चर्चा हुई। सचिव ने भूमि अधिग्रहण और वन-व्यपवर्तन के लंबित मामलों की जानकारी समय पर उच्च कार्यालयों को देने को कहा।

सड़क सुरक्षा पर जोर

श्री बंसल ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सड़क सुरक्षा के मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मानकों के अनुरूप ही गति अवरोधक बनाने को कहा। अधिकारियों को फील्ड में जाकर कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

गुणवत्ता से समझौता नहीं

ठेकेदारों की बैठक में सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय पर कार्य पूणर्ता में कोई समझौता नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में अच्छा काम होना चाहिए।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी अभिजीत कुमार, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार, मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप और अधीक्षण अभियंता एस.एस. माझी सहित पांचों राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग के अधिकारी मौजूद थे।

सैनिक स्कूल अंबिकापुर में आधुनिक पीवीसी बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

सैनिक स्कूल अंबिकापुर में नव-निर्मित अत्याधुनिक पीवीसी बैडमिंटन कोर्ट का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल ने कोर्ट का लोकार्पण किया। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सरगुजा अजीत वसंत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

कैप्टन विक्रम बत्रा को दी पुष्पांजलि

समारोह का शुभारंभ परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद अतिथियों ने देश के वीर सैनिकों के सम्मान में स्थापित ह्यपरमवीर गैलरीह्व का भी लोकार्पण किया। गैलरी में परमवीर चक्र विजेताओं के साहस और बलिदान की प्रेरक गाथाओं को प्रदर्शित किया गया है।

खेल से होगा सर्वांगीण विकास

मंत्री राजेश अग्रवाल ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेल अधोसंरचना विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाती है। विद्यालय प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधाएं भविष्य के खिलाड़ियों और नेतृत्वकर्ताओं के निर्माण में सहायक होंगी। उद्घाटन के दौरान नव-निर्मित बैडमिंटन कोर्ट पर प्रदशर्नी मैचों का आयोजन किया गया। कैडेट्स ने उत्साह से भाग लेते हुए अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के आत्मविश्वास ने अतिथियों को प्रभावित किया।

राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे प्रदर्शन

विद्यालय की प्राचार्या कर्नल रीमा सोबती ने बताया कि पीवीसी बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण से कैडेट्स को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, कमर्चारी और बड़ी संख्या में कैडेट्स मौजूद रहे। नव-निर्मित खेल सुविधा और परमवीर गैलरी का लोकार्पण सैनिक स्कूल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बाल संरक्षण आयोग पहल से दो छात्राओं को मिली राहत, एमजे स्कूल ने माफ की फीस

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष अधिवक्ता सौरभ चौबे के माध्यम से प्रस्तुत किए गए एक संवेदनशील प्रकरण में दो छात्राओं एवं उनकी गंभीर रूप से बीमार मां को महत्वपूर्ण राहत मिली है। आयोग के हस्तक्षेप, समन्वय और दोनों पक्षों की सहमति से एमजे स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं की संपूर्ण बकाया फीस माफ करने तथा 21-21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण में आवेदिका रेखा रामटेके अपनी पुत्री नित्या के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित हुईं। उन्होंने बताया कि उनके पति द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद परिवार गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक संकट से गुजर रहा है। स्वयं आवेदिका गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तथा उपचार एवं जीवन-यापन की परिस्थितियों के कारण उन्हें अपनी दोनों पुत्रियों के साथ दूसरे शहर में जाकर निवास करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वे एमजे स्कूल में बच्चियों की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल संरक्षण आयोग द्वारा विशेष एवं त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की गई। लगातार दो दिनों तक सुनवाई कर दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया। सुनवाई के दौरान स्कूल संचालिका डॉ. श्रीलेखा विरूलकर, प्राचार्य मनप्रीत फलमाली तथा प्रबंधक उज्जवल कुमार उपस्थित रहे। स्कूल प्रबंधन ने आयोग को बताया कि उन्हें आवेदिका के पति की आत्महत्या तथा उनकी गंभीर बीमारी की जानकारी पूर्व में नहीं थी।

बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट किया कि आयोग किसी भी पक्ष पर अनावश्यक दबाव बनाकर निर्णय नहीं चाहता है। आयोग का उद्देश्य बच्चों के सवोर्त्तम हितों की रक्षा करते हुए न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाधान निकालना है। इसी दृष्टिकोण से दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित कर सहमति आधारित समाधान तैयार किया गया।

आयोग के सुझाव पर स्कूल प्रबंधन ने दोनों छात्राओं नित्या एवं तृप्षा की समस्त बकाया फीस माफ करने, तत्काल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) एवं अंकसूची उपलब्ध कराने तथा नई जगह पर प्रवेश में सहायता हेतु 21-21 हजार रुपये की स्वैच्छिक आर्थिक सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। यह भी तय हुआ कि 25 जून 2026 को छात्राओं को टीसी एवं अंकसूची प्रदान कर दी जाएगी तथा सात दिनों के भीतर सहायता राशि आवेदिका के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

अधिवक्ता सौरभ चौबे ने कहा कि यह आदेश केवल एक परिवार को राहत प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में प्रदेश के विद्यालयों एवं अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती, तो बाल संरक्षण आयोग उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम था, जिसका प्रभाव स्कूल प्रबंधन पर अधिक गंभीर हो सकता था। यह आदेश आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि असाधारण मानवीय परिस्थितियों में बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा शिक्षा संस्थानों को भी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। आवेदिका द्वारा किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता न बताए जाने पर आयोग ने प्रकरण का निराकरण कर दिया।

जनजाति क्षेत्रों के युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण और रोजगार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की समन्वय सह निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के गरीब युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग के लोगों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के जरिए रोजगार देने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने जनजाति समूहों, वंचित वर्गों और गरीब युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने के लिए व्यापक कायर्योजना बनाने के निर्देश दिए।

गैर-लाभकारी कंपनी का होगा गठन

बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बीच एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। यह संस्था अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समुदायों के युवाओं, महिलाओं तथा तृतीय लिंग के

लोगों को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के जरिए सशक्त बनाएगी।

बस्तर-सरगुजा में खुलेगा कल्याण गुरुकुल

फाउंडेशन के अधिकारियों ने बताया कि झारखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासी बहुल जिलों में कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज खोले जाएंगे। स्थानीय आईटीआई और छात्रावासों को आवासीय प्रशिक्षण केंद्र गुरुकुल में बदला जा रहा है।

ट्रेनिंग के बाद मिलेगी पक्की नौकरी

युवाओं को उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही कंपनियों से करार किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण पूरा होते ही युवाओं को पक्की नौकरी मिल सके। कंस्ट्रक्शन और मैनुफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में शॉर्ट टर्म आवासीय ट्रेनिंग दी जा रही है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम भी किया जा रहा है।

स्कूल छोड़ने वालों पर विशेष जोर

इस कार्यक्रम का विशेष जोर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों, ग्रामीण युवाओं और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर है। प्रशिक्षण के तुरंत बाद रोजगार देकर आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, पर्यटन सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव राजेन्द्र कुमार कटारा सहित पंचायत, कौशल विकास विभाग और फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे।

राज्यपाल ने प्रारंभ पत्रिका के विशेषांक का किया विमोचन

विषय : जनजातीय ज्ञान और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने मंगलवार को सोसायटी फॉर एम्पावरमेंट द्वारा प्रकाशित पत्रिका प्रारंभ के विशेषांक का विमोचन किया। इस विशेषांक का संपादन डॉ. रूपेन्द्र कवी, उपसचिव, संवैधानिक प्रकोष्ठ, लोकभवन रायपुर ने किया है।

जनजातीय ज्ञान पर केंद्रित है विशेषांक

यह विशेषांक ह्यप्राकृतिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में जनजातीय ज्ञान की प्रासंगिकताह्व विषय पर आधारित है। इसमें जनजातीय समुदायों के परंपरागत ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है।

राज्यपाल ने दी बधाई

विमोचन के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने पत्रिका की विषयवस्तु की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अंक वतर्मान पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। राज्यपाल ने संपादकीय टीम को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

संपादकीय

रोजगार, स्वरोजगार भी अच्छी सरकार का पैमाना

किसी भी अच्छी सरकार के लिए जो पैमाना होता है, उसमें कई बातों के अलावा इस बात पर खास जोर दिया जाता है कि उसने रोजगार व स्वरोजगार के लिए क्या किया। बेरोजगारी किसी राज्य व देश में आजादी के बाद से गंभीर समस्या रही है कि क्योंकि हमारे यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है और सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उससे कम रहते है, इससे देश हो या कोई राज्य हो,वहां रोजगार की समस्या तो रहती ही है। इसलिए हर राज्य की सरकार को अच्छी सरकार की कसौटी पर कसने के लिए यह जरूर देखा जाता है कि सरकार ने रोजगार व स्वरोजगार के लिए क्या कुछ किया है ।रोजगार व स्वरोजगार ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते हैं तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी होता है। यही वजह है साय सरकार ने भी अन्य सरकारों की तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ावा देने का फैसला किया है ताकि यहां के लोगों की आय बढ़े,उनका जीवनस्तर ऊंचा हो,राज्य विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग कर सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए साय सरकार ने तीन फैसले किए हैं। कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को हर साल 125 दिन काम वीजी जीरामजी योजना के तहत निश्चित रूप से दिया जाएगा,इसके अलावा गांवों में अटल आजीविका समृध्दि हाट स्थापित किए जाएंगे। नई कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) नीति-2026 को मंजूरी दी गई है। कोई भी योजना जब केंद्र व राज्य के सहयोग चलाई जाती है तो और दोनों जगह एक ही दल की सरकार को हो योजना के सफल होने के ज्यादा मौके रहते है क्योंकि इससे दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं इससे दोनों को लाभ होता है और जनता को भी इसका फायदा होता है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीजी जीरामजी योजना में राज्य के पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन अकुशल श्रम आधारित रोजगार मुहैया कराया जाएगा।

इसमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है इससे फायदा यह होगा कि राज्य सरकार इस योजना के सफल क्रियान्वयन की और पहले से ज्यादा ध्यान देगी। पहले पूरा पैसा केंद्र को होने के कारण राज्य सरकारे इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचान ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब राज्य का खुद का पैसा लगेगा तो राज्य इस पर गंभीरता से अमल हो इस ओर पूरा ध्यान देगा तो लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। पहले पैसे के केंद्र से आने का इंतजार किया जाता था, अब पैसे का प्रावधान राज्य के बजट में होने से पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पैसे से संबंधित जो दिक्कतें पहले होती थी अब नहीं होंगी। राज्य सरकार ने बजट में इसके लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी जीरामजी योजना के तहत चार हजार करोड़ के रुपए के काम कराए जाएंगे, इसमें जल सरंक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन,ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण और आजीविका परिसंपत्तियों के जुड़े विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका कई तरह से लाभ मिलेगा।

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कई तरह के कारोबार की जरूरत होती है और कारोबार की सफलता के लिए एक बाजार का होना भी जरूरी होता है किसी क्षेत्र में कई तरह के कारोबार रहने से कारोबार नहीं बढ़ता है, कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बाजार भी जरूरी होता है ।बाजार होने से कारोबार बढ़ता है, खरीदार खरीदारी के लिए आते हैं। साय सरकार की अटल हाट से क्षेत्र का कारोबार बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अटल आजीविका समृद्दि योजना शुरू करेगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा,बुनाई,सिलाई,हस्तशिल्प,जैसे सृजन केंद्र,दलहन-तिलहन प्रसंस्करण इकइयां, कोल्ड स्टोरेज व अटल डिजिटल केंद्र स्थापित किए जाएँगे। वहीं नई कंप्रेस्ट बायोगैस नीति-26 से कृषि अवशेष,नगरीय ठोस अपशिष्ट,पशुधन अपशिष्ट व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर स्वच्छ ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। इससे अपशिष्ट प्रबंधन सुधरेगा व ग्रीम हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे कई तरह की समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से तीन समस्याएं ऐसी रही हैं जिनके समाधान की जरूरत थी और कई राज्य सरकारों के प्रयास के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। यह तीन पुरानी समस्याएं हैं गांवों से लोगों का रोजगार के लिए पलायन, उत्पादों की कम कीमत मिलना, कृषि अवशेष के निस्तारण नहीं होना। साय सरकार की नई नीति से लोगों को रोजगार मिलेगा,इससे आय बढ़ेगी, लोगों का पलायन नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकों के सामने अपने उत्पादन के भंडारण की समस्या होती थी, इससे उनको कम दाम पर अपना सामान बेचना पड़ता था, भंडारण व कोल्डस्टोरेज की व्यवस्था होने लोगों को उत्पादों का ज्यादा दाम मिलेगा। जहां तक बायो गैस उत्पादन का सवाल है तो ईरान अमरीका युध्द के दौरान ऊर्जा के दूसरे विकल्पों की जरूरत महसूस हुई और बायोगैस बनने गांवों में कम से कम ऊर्जा संकट के समय ऊर्जा की कमी तो नहीं होगी। इससे एलपीजी खपत में कमी आएगी। फिर कभी ऊर्जा संकट आया तो राज्य उसके लिए तैयार रहेगा और राज्य पर उस संकट का असर कम होगा। साय सरकार के प्रयासों राज्य को विकसित राज्य बनाने में सफलता मिलेगी और राज्य सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने मे मोदी सरकार का पूरा सहयोग कर सकेगी।

आपातकाल का अंत कितना भयावह : लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा

सौरभ वार्ष्णेय

25 जून 1975 की आधी रात का काला अध्याय कैसे कोई भूल सकता है? गर्मी, तपिश और आंधी ने तो जनमानस को पहले से ही झुलसा रखा था ऊपर से रेडियो पर आया संदेश से पूरा देश सकते में आ गया। आपातकाल न तो पढ़ा था न पहले कभी देखा था अचानक आए राजनीतिक तूफान ने देश में अफरातफरी मचा दी। देश में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है। लगभग 21 महीनों तक चले इस दौर ने न केवल राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं, अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किए। मार्च 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ, तब देश ने राहत की सांस तो ली, लेकिन इसके पीछे छिपी पीड़ा, भय और लोकतांत्रिक संस्थाओं को हुई क्षति लंबे समय तक महसूस की गई।आपातकाल का अंत इसलिए भी भयावह कहा जाता है क्योंकि उस समय तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता काफी कमजोर हो चुकी थी। संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर सत्ता का प्रभाव बढ़ गया था। जनता के अधिकार सीमित हो गए थे और भय का वातावरण बन गया था। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि यदि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा न हो तो शासन निरंकुशता की ओर बढ़ सकता है।

आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। अखबारों को सरकारी अनुमति के बिना समाचार प्रकाशित करने की स्वतंत्रता नहीं थी। विरोधी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया। लोकतंत्र की आत्मा मानी जाने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई थी।

आपातकाल के अंतिम चरण में सबसे अधिक आलोचना जबरन नसबंदी अभियान और झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाईयों को लेकर हुई। कई स्थानों पर प्रशासनिक दबाव में लोगों को नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। गरीब और कमजोर वर्ग इस नीति का सबसे बड़ा शिकार बना। इससे जनता में व्यापक असंतोष पैदा हुआ। अनेक परिवारों ने सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट झेले, जिसकी पीड़ा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।

आपातकाल का अंत इसलिए भी भयावह कहा जाता है क्योंकि उस समय तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता काफी कमजोर हो चुकी थी। संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर सत्ता का प्रभाव बढ़ गया था। जनता के अधिकार सीमित हो गए थे और भय का वातावरण बन गया था। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि यदि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा न हो तो शासन निरंकुशता की ओर बढ़ सकता है।

हालांकि, मार्च 1977 के आम चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को भी साबित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चुनाव कराने का निर्णय लिया और जनता ने मतदान के माध्यम से अपना फैसला सुनाया। पहली बार केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। यह लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण क्षण था।आपातकाल की समाप्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों से गहरा लगाव रखती है। सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जनता ही सवोच्च होती है। इस दौर ने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। आज, आपातकाल के पांच दशक बाद भी यह घटना एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में याद की जाती है। इसका संदेश स्पष्ट है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि नागरिक अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन से मजबूत होता है। आपातकाल का अंत भयावह अनुभवों और लोकतंत्र की पुनर्जागृति दोनों का प्रतीक था। यह इतिहास हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को सदैव सजग रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जागरूक नागरिक ही होते हैं।

आपातकाल के काले छींटे कब सुलझेंगे?

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसे आज भी काला अध्याय कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और अभिव्यक्ति की आजादी पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए थे। लगभग 21 महीने तक चले इस दौर में हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विरोध के हर स्वर को दबाने का प्रयास किया गया।

आज, आपातकाल समाप्त हुए पाँच दशक के करीब समय बीत चुका है, लेकिन उसके काले छींटे पूरी तरह धुल नहीं पाए हैं। इसका कारण केवल इतिहास की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र को लेकर लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां भी हैं। जब भी सत्ता के केंद्रीकरण, संस्थाओं की स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विपक्ष की भूमिका पर बहस होती है, तब आपातकाल की याद स्वतः ताजा हो जाती है। आपातकाल का सबसे बड़ा सबक यह था कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष मीडिया और जागरूक नागरिकों से संचालित होता है। यदि इनमें से किसी भी स्तंभ को कमजोर किया जाता है तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए आपातकाल की घटनाओं का स्मरण केवल अतीत को कोसने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है।दुर्भाग्य से, आपातकाल पर राजनीतिक दल अक्सर अपने-अपने दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं। एक पक्ष इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताता है, जबकि दूसरा पक्ष वतर्मान परिस्थितियों की तुलना उस दौर से करने का प्रयास करता है। इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच वास्तविक आवश्यकता यह है कि देश उस कालखंड का निष्पक्ष मूल्यांकन करे और उससे मिले सबकों को आत्मसात करे।

आपातकाल के काले छींटे तभी पूरी तरह सुलझेंगे जब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समाज और शासन दोनों की प्रतिबद्धता अटूट होगी। नागरिक अधिकारों का सम्मान, सत्ता की जवाबदेही, प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती ही उस अंधकारमय दौर की पुनरावृत्ति को रोक सकती है। इतिहास को भुलाना समाधान नहीं है; उससे सीख लेकर लोकतंत्र को और मजबूत बनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि आपातकाल को केवल राजनीतिक विमर्श का विषय न बनाया जाए, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का स्थायी पाठ बनाया जाए। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होगा तथा शासन संविधान की मर्यादाओं के भीतर कार्य करेगा, तभी आपातकाल के वे काले छींटे वास्तव में मिट सकेंगे और भारत का लोकतंत्र और अधिक परिपक्वतथा सशक्त बन सकेगा।

मानसून बिगड़ा तो देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई पर असर संभव

अशोक भाटिया

भारतीय रिजर्व बैंक के जून बुलेटिन में प्रकाशित स्टेट ऑफ द इकोनॉमी लेख में कहा गया है कि यदि दक्षिण-पश्चिम मानसून उम्मीद के मुताबिक नहीं रहता, तो इसका असर देश की आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर पड़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत स्थिति में है, लेकिन कृषि और ग्रामीण मांग काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे में कमजोर बारिश खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकती है, जिससे महंगाई बढ़ने और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर असर पड़ने की आशंका पैदा हो सकती है।

लेख में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक माहौल अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। पश्चिम एशिया में हाल के अंतरिम शांति समझौते से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में आर्थिक जोखिम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं और यदि मौजूदा समझौते कमजोर पड़ते हैं या तनाव फिर बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक बाजारों और निवेश गतिविधियों पर दिखाई दे सकता है।

इस समय मानसून का इंतजार कर रहे किसानों के साथ-साथ मानसून की राह देख रहे उत्तर भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि मानसून अपने समय से लेट हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून एक सप्ताह की देरी से आ सकता है। स्काईमेट का दावा है कि उत्तर भारत में मानसून आने में देर हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार वह कमजोर रहने वाला है, जबकि प्री-मानसून में भी बारिश बहुत कम हुई है। इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर चार माह के लिए बारिश के मौसम की शुरुआत होती है। लेकिन इस बार आठ जून को मानसून के केरल तट पहुंचते की संभावना जताई गई थी।

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से भारतीय मानसून को अल-नीनो ने कमजोर करते आ रहा था। कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के कारण मानसून यहां की कृषि और अर्थव्यवस्था, दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। वास्तव में, मानसून के आसपास भारतीय अर्थव्यवस्था घूमती है। मानसून असफल रहता है तो देश के विकास और अर्थव्यवस्था पर विपरित प्रभाव पडेग़ा। दरअसल, एक खराब मानसून न केवल तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को कमजोर करता है, बल्कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं के आयात को भी बढ़ावा देता है, और सरकार को कृषि ऋण छूट जैसे उपाय करने को भी मजबूर करता है। जिससे सरकार पर वित्त का दबाव बढ़ जाता है।

वातावरण में आ रहे बदलावों ने बीते कुछ दशकों के दौरान मानसून के मिजाज को बदल डाला है। विशेषज्ञों को लग रहा है कि हमें अपनी खेती में बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। उनका मानना है कि अगर जल्द ही हमारी खेती ने मानसून के बदले मिजाज के साथ तालमेल नहीं बिठाया तो एक अरब से ज्यादा आबादी वाले हमारे देश में अभूतपूर्व खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। जाहिर है, जिस तरह से सिंचाई भगवान भरोसे है और ग्लोबल वार्मिंग से बारिश का चक्र बदल रहा है। उसका सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है।

इससे राष्ट्रीय आय में गिरावट के चलते सरकार का राजस्व तेजी से गिरावट आ सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि राज्य का राजस्व और आय हर साल मॉनसून पर निर्भर करती है। इन्हीं वजहों से कहा जाता है कि मॉनसून का भारतीय अर्थव्यवस्था से गहरा नाता है। यदि मानसून कमजोर रहा तो देश के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कृषि उत्पाद पर असर पड़ सकता है। पैदावार पूरी तरह प्रभावित होने से महंगाई का बढ़ना निश्चित है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था में प्राण फूंकने की कोशिशों को करारा झटका लग सकता है। वहीं ग्रामीण आमदनी और उपभोक्ता के खर्च के लिए मौसमी बारिश अहम कारक है। देश की दो-तिहाई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां कृषि ही आय का मुख्य स्रोत है। मानसून को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उनसे लग रहा है कि परिस्थितियां डराने वाली होंगी।

वास्तव में किसानों के लिए गर्मी के मौसम की बारिश बड़ी अहमियत रखते है क्योंकि देश के केवल 40 फीसद कृषि क्षेत्र के बारे में कहा जा सकता है कि वहां सिंचाई की सुविधाएं हैं और एकाध मानसून में वह गड़बड़ी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन शेष 60 फीसद इलाका मानसून पर ही निर्भर होता है। ऐसे में बारिश सामान्य से कम हुई तो मुश्किल होना स्वाभाविक है। यों कहें बारिश और खाद्यान्न उत्पादन का कीमतों से सीधा संबंध है। कम बारिश और उच्च मंहगाई का रिश्ता स्पष्ट दिखाई देता है। चूंकि देश के 14 करोड़ से अधिक परिवार खेती पर निर्भर है, इसलिए कम बारिश की स्थिति में खेती-किसानी से जुड़े अधिकांश छोटे किसानों का जीवन सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो कहा जा सकता है कि अभी भी भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है।

भारतीय खाद्यान्नों की शत-प्रतिशत पूर्ति यहां होने वाली कृषि से ही होती है, जो पूर्णतया खेती की सफलता पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, देश के 22 करोड़ पशुओं को चारा भी कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि के न होने या अत्याल्पावस्था में हो पाने की स्थिति में पशुओं से प्राप्त होने वाली आय तथा सुविधाओं में कमी आ जाती है। इस तरह मानसून के प्रतिकूल होने पर देश में खाद्यान्नों तथा कृषि से संबंद्ध विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल विदेशों से मांगना पड़ता है, जिसके लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का व्यय होता है। मौसम अनुकूल रहता है तो इन्हीं उत्पादों का विदेशों को निर्यात कर बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हो जाती है।

वातावरण में आ रहे बदलावों ने बीते कुछ दशकों के दौरान मानसून के मिजाज को बदल डाला है। विशेषज्ञों को लग रहा है कि हमें अपनी खेती में बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। उनका मानना है कि अगर जल्द ही हमारी खेती ने मानसून के बदले मिजाज के साथ तालमेल नहीं बिठाया तो एक अरब से ज्यादा आबादी वाले हमारे देश में अभूतपूर्व खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। जाहिर है, जिस तरह से सिंचाई भगवान भरोसे है और ग्लोबल वार्मिंग से बारिश का चक्र बदल रहा है। उसका सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है। बेशक, दिन प्रतिदिन हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। 2050 में 1.6 से 1.7 अरब भारतीयों का पेट भरने के लिए हमें 45 करोड़ टन खाद्यान्न की जरूरत होगी यानी मौजूद से दुगना। ऐसे में बिना सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के सिर्फ मानसून भरोसे इसे हासिल करना असंभव है। यह विडंबना है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम मानसून पर निर्भरता कम नहीं कर पाए।

मोबाइल की लत में खोती याददाश्त : एक गंभीर चेतावनी

सत्यभूषण शर्मा

वर्तमान डिजिटल युग में मोबाइल फोन मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। संचार, शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, खरीदारी और सामाजिक संपर्क जैसे लगभग सभी कार्य अब मोबाइल के माध्यम से संपन्न होने लगे हैं। तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक अवश्य बनाया है, किंतु इसके अंधाधुंध उपयोग ने अनेक नई समस्याओं को भी जन्म दिया है। इनमें सबसे चिंताजनक समस्या है—मोबाइल की बढ़ती लत और उससे प्रभावित होती मानव स्मरण शक्ति अर्थात याददाश्त।

आज का दृश्य अत्यंत सामान्य हो गया है कि लोग अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों अथवा सहकमिर्यो के मोबाइल नंबर तक याद नहीं रखते। जन्मदिन, महत्वपूर्ण तिथियां, आवश्यक सूचनाएं और यहां तक कि दैनिक कार्यों की सूची भी मोबाइल पर निर्भर हो गई है। परिणामस्वरूप मस्तिष्क की स्वाभाविक स्मरण क्षमता का उपयोग लगातार कम होता जा रहा है। जिस कार्य के लिए पहले व्यक्ति अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता था, अब वही कार्य मोबाइल फोन कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब हम किसी जानकारी को स्वयं याद रखने के बजाय मोबाइल में सुरक्षित कर देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस जानकारी को लंबे समय तक संग्रहित करने का प्रयास नहीं करता। धीरे-धीरे यह आदत स्मृति क्षमता को कमजोर करने लगती है। मोबाइल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को भूलने लगता है और उसकी एकाग्रता भी प्रभावित होती है। ०मोबाइल की लत का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। घंटों तक सोशल मीडिया, वीडियो गेम, शॉर्ट वीडियो और मनोरंजन सामग्री देखने के कारण उनका ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है। निरंतर स्क्रीन देखने से मस्तिष्क को पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप पढ़ी हुई बातें जल्दी भूल जाना, ध्यान केंद्रित न कर पाना और मानसिक थकान जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विद्यार्थी किसी तथ्य को समझने या याद रखने के बजाय तुरंत इंटरनेट पर खोज लेते हैं। इससे उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता तथा स्मरण शक्ति का विकास बाधित होता है। परीक्षा के समय ऐसे विद्यार्थियों को विषयवस्तु याद रखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

मोबाइल की अत्यधिक लत केवल याददाश्त को ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, संदेश और सोशल मीडिया अपडेट मस्तिष्क को हर समय सक्रिय रखते हैं। इससे तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद न मिलने से स्मरण शक्ति और अधिक कमजोर हो जाती है।

पारिवारिक जीवन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पहले परिवार के सदस्य आपस में संवाद करते थे, अनुभव साझा करते थे और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के विकास और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक होती थी। आज परिवार के अनेक सदस्य एक ही कमरे में बैठकर भी अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। संवादहीनता का यह वातावरण मानसिक विकास के लिए चिंता का विषय है।

मोबाइल की लत से बचने के लिए संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल-मुक्त गतिविधियों के लिए निर्धारित करना चाहिए। पुस्तक पढ़ना, लेखन करना, पहेलियां हल करना, गणितीय अभ्यास करना, कविता याद करना, शारीरिक व्यायाम और ध्यान-योग जैसी गतिविधियां स्मरण शक्ति को सुदृढ़ बनाती हैं। बच्चों के स्क्रीन टाइम पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए तथा उन्हें रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना चाहिए।

विद्यालयों और अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को तकनीक के लाभों के साथ-साथ उसके दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जाना चाहिए। डिजिटल साक्षरता के साथ डिजिटल अनुशासन की शिक्षा समय की मांग है।

मोबाइल फोन आधुनिक जीवन की आवश्यकता है, किंतु आवश्यकता और निर्भरता के बीच की सीमा को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम तकनीक के स्वामी बनने के बजाय उसके गुलाम बन जाएंगे, तो हमारी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। इसलिए आवश्यक है कि मोबाइल का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए, ताकि तकनीक हमारे विकास का साधन बने, हमारी क्षमताओं के ह्रास का कारण नहीं।

बढ़ती आर्थिक चुनौतियां

वित्त मंत्रालय के मुताबिक तीन कारणों से दुनिया नया आकार ले रही है : महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी गठबंधन में दरार, और मैनुफैक्चरिंग में चीन का वर्चस्व। इसके अनुरूप ढलने के लिए भारत के पास बहुत कम वक्त है।

बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए बदलावों से तालमेल बनाने के लिए भारत के पास एक बहुत छोटी खिड़की मौजूद है। यह बात केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्थायी संसदीय समिति के सामने कही। बताया गया कि चीन ने अपने नए कानून के तहत वहां स्थित आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है। वहां से अपने कारखाने हटाने वाली कंपनियों को वह दंडित कर रहा है। इससे भारत में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीति के सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस समय ये तीन परिघटनाएं दुनिया को नया आकार दे रही हैः बड़ी ताकतों में प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी गठबंधन में दरार, और मैनुफैक्चरिंग में चीन का प्रभुत्व।

मंत्रालय ने कहा कि इन परिवतर्नो पर भारत को अधिक फुर्तीला और रणनीतिक प्रतिक्रिया दिखानी होगी। ऐसा करने के लिए देश के पास 'बहुत छोटा अवसरङ्ग है। मंत्रालय ने कहा कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के तहत व्यापार, तकनीक, और वित्त का उपयोग सामान्य लाभ उठाने के बजाय रणनीतिक हितों के मुताबिक किया जा रहा है। इसी क्रम में चीन ने अपने यहां से कारखाना, तकनीक, या विशेषज्ञों को दूसरे देशों में- खासकर भारत ले जाने की राह में कानूनी रुकावट खड़ी कर दी है। भारत में साझा उद्यम या देशी निवेश के तहत लगाए जा रहे कारखानों की इन मामलों में चीन पर निर्भरता रही है। स्पष्टतः ये दोनों परिघटनाएं भारत के लिए चुनौती बनकर आई हैं।

हालांकि यूरोप और अमेरिका के बीच पड़ती दरार को वित्त मंत्रालय ने भारत के लिए अवसर के रूप में देखा है, मगर इसका लाभ उठाने के लिए तुरंत खुद को तैयार करने की चुनौती उसके सामने है। मंत्रालय ने माना कि इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है। कहा जा सकता है कि वित्त मंत्रालय को बदल रही दुनिया का सही अहसास है। मगर, नई परिस्थितियों के मुताबिक नजरिए एवं नीतियों में जिस तरह के आमूल परिवर्तन की जरूरत है, उसकी समझ का संकेत उसने नहीं दिया है। क्या बिना घरेलू बाजार के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किए, नए बाहरी हालात का मुकाबला किया जा सकता है- यह बुनियादी सवाल है।

घर पर कंपोस्ट तैयार करते समय ना करें ये गलतियां

आर्गेनिक कंपोस्ट को प्लांट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसलिए अधिकतर लोग घर पर ही कंपोस्ट तैयार करते हैं। हालांकि, इस दौरान आपको कुछ छोटी-छोटी गलतियों से बचना चाहिए।

जब प्लांट की केयर करते समय उसमें खाद मिलाई जाती है तो यह मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। इससे उसमें पोषक तत्व बहाल होते हैं और प्लांट ग्रोथ पर पॉजिटिव असर पड़ता है। यूं तो आपको मार्केट में भी खाद आसानी से मिल जाती है, लेकिन घर पर खाद बनाना अधिक बेहतर उपाय माना जाता है। इससे ना केवल लैंडफिल के कचरे को कम करने में मदद मिलती है, बल्कि यह पॉकेट फ्रेंडली भी है। इतना ही नहीं, फल व सब्जियों के छिलकों से बनी खाद प्लांट के लिए अधिक बेहतर मानी जाती है। यूं तो खाद बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी इस दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। अमूमन घर पर खाद तैयार करते समय लोग कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बता रहे हैं-

एयरेशन पर ध्यान ना देना

खाद बनाने के लिए ऑक्सीजन की बेहद जरूरी होती है। अन्यथा खाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री डिकंपोस्ट नहीं होती है। जब आप को नियमित रूप से पलटते नहीं हैं या फिर पर्याप्त हवा न होने की स्थिति में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे खाद बनाने की प्रक्रिया एयरेशन की कमी हो जाती है। इससे खाद में अजीब सी स्मेल आती है।

मैटीरियल को छोटे-छोटे टुकड़ों में ना तोड़ना

कुछ लोग खाद बनाते समय सामग्री को सीधे ही कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। यह एक ऐसी गलती है, जो खाद बनने के प्रोसेस को काफी धीमा कर देती है। दरअसल, छोटे पार्टिकल्स तेजी से डिकंपोज होते हैं। अगर आपकी सामग्री के टुकड़े बड़े हैं तो इससे खाद बनने में आवश्यकता से बहुत अधिक समय लग सकता है।

बहुत गीला या बहुत सूखा होना

खाद का बहुत गीला या बहुत सूखा होना दोनों ही नुकसानदायक माना जाता है। इससे डिकंपोजिशन प्रोसेस में बाधा आ सकती है। इसलिए आपको खाद के मॉइश्चर लेवल का खासतौर पर ध्यान रखना होता है। ध्यान दें कि खाद में निचोड़े हुए स्पंज की नमी जितना मॉइश्चर होना चाहिए।

गलत चीजों को शामिल करना

यह तो हम सभी जानते हैं कि कंपोस्ट में वेस्ट मैटीरियलको शामिल किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी भी आइटम को कंपोस्ट बिन में कुछ भी डाल दें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें खाद में शामिल नहीं करना चाहिए, मसलन-मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, पालतू का वेस्ट या फिर ऑयल आइटम्स आदि। दरअसल, जब आप ऐसा करते हैं तो इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। ये चीजों पेस्ट को भी आकर्षित कर सकती हैं और इनसे गंध पैदा होती है।

बहुत जल्दबाजी करना

खाद बनना एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसमें काफी समय लगता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो इससे खाद की क्वालिटी पर असर पड़ता है। ध्यान दें कि तापमान और सामग्री के आकार जैसे कारक इस प्रोसेस पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए, थोड़ा सब्र करें और खाद को बनने के लिए पर्याप्त समय दें। तो अब आप भी घर पर खाद तैयार करते समय इन छोटी-छोटी गलतियों से बचें और अपने प्लांट की बेहतर केयर करें।

ऐसे रखें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल

लगातार जॉब सर्च करना काफी थका देने वाला होता है। कई बार इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन कुछ छोटे-छोटे टिप्स अपनाकर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। जॉब हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसलिए हम सभी एक अच्छी जॉब पाने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि, जब लगातार जॉब सर्च करने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिलती है तो इससे ना केवल वित्तीय बोझ बढ़ जाता है, बल्कि इससे मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर देखने को मिलता है।

जब बार-बार कोशिश करने के बाद भी हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो इससे हम काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में मन में सिर्फ नेगेटिव ख्याल ही आते हैं। जब हम लगातार नेगेटिव बातें सोचते हैं तो इससे मेंटल हेल्थ बहुत अधिक इफेक्ट होती है। हालांकि, अगर आप कुछ आसान छोटे-छोटे आसान उपाय अपनाते हैं तो ऐसे में इस नेगेटिविटी के बीच भी आपको अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में मदद मिल सकती है-

सेट करें रूटीन

जॉब ना मिलने और लगातार जॉब सर्च करने के दौरान जब मन में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है तो उसे दूर करने का एक आसान तरीका होता है कि आप अपने दिन का एक रूटीन सेट करें। जिसमें आप जॉब सर्चिंग के अलावा सेल्फ केयर एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज या फिर हॉबीज आदि को थोड़ा समय दें। जब आप अपनी दिनचर्या में उन चीजों को भी शामिल करते हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है तो इससे मन को काफी अच्छा लगता है और मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव असर पड़ता है।

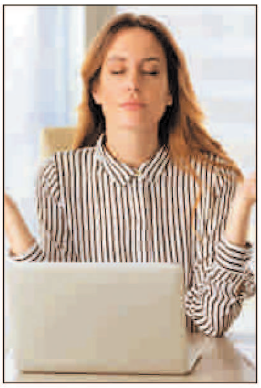

फैमिली से लें सपोर्ट

आपको यह समझना चाहिए कि दुनिया में आप अकेले नहीं है, जो इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो। ऐसे में अपने मन की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप फैमिली, दोस्त या फिर किसी करीबी की मदद लें। आप उनसे अपने मन की परेशानी शेयर करें। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका मन काफी हल्का हो जाता है और आप काफी रिलैक्स महसूस करते हैं।

नेटवर्किंग की लें मदद

अगर लगातार सर्च करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको नेटवर्किंग की मदद लेनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी खास फील्ड में ही मंदी आती है। ऐसे में उस फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छी जॉब मिलने में परेशानी होती है। इसलिए, जब आप अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स से जुड़ते हैं तो इससे आपको स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है और इस तरह आप अधिक बेहतर तरीके से स्थिति को समझ पाते हैं। जिससे आपके मन की नेगेटिविटी भी दूर होती है।

सेट करें रियलिस्टिक गोल्स

जॉब ढूंढना और उसे हासिल करना किसी जंग से कम नहीं है। शायद यही कारण है कि इस जर्नी में अक्सर लोगों को काफी निराशा होती है। इसलिए, यह बेहद जरूरी है कि आप कुछ रियलिस्टिक गोल्स सेट करें और थोड़ा सब्र भी करें। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो तुरंत रिप्लाई की उम्मीद ना करें। साथ ही साथ, एक ही कंपनी में अप्लाई करने की जगह आप अलग-अलग कंपनियों में आवेदन करें। इससे आपको जॉब मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और आपके मन की निराशा भी दूर होती है।

कहीं आपके फोन डाटा पर तो नहीं किसी की पैनी नजर

क्या आपका फोन चलते-चलते अचानक स्विच ऑफ, रीस्टार्ट, स्पीड का स्लो होने जैसी प्रॉब्लम तो नहीं होती अगर ऐसा है तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका फोन सेफ है या नहीं।

बदलते दौर में लोगों के अंदर मोबाइल फोन का क्रेज बखूबी देखा जा सकता है। आज बच्चे-बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन देखने को मिल जाता है। डिजिटल वर्ल्ड यानी आज के दौर में लोग बिना फोन के एक कदम नहीं बढ़ाते हैं। बात करने से लेकर, किसी को पैसे देने तक का सारा डाटा फोन में सेफ होता है। हमारी सारी डिटेल्स सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा हमारे डाटा के चोरी होने का होता है। बात केवल चोरी होने की नहीं बल्कि आज के समय में डाटा का मिस यूज काफी बढ़ गया है जिसके कारण इंसान अपने ही घर में बैठे-बैठे कब ठगी का शिकार हो जाता है उसे खुद ही पता नहीं चलता। कंप्यूटर के मुकाबले मोबाइल को हैक करना बेहद ही आसान काम है। ऐसे में अपने फोन के बारे में अपडेट रहना बहुत आवश्यक है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका यूज कर आप अपने फोन को सेफ रख सकते हैं।

अनजान एप को फोन से तुरंत करें डिलीट

कई बार फोन में हमें कोई अनजान एप डाउनलोड मिलता जिसे देखकर यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यह कैसे डाउनलोड हो गया। अगर आपके फोन कभी-भी ऐसा अनजान ऐप दिखें तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। इन ऐप में खतरनाक मैलवेयर भी हो सकते हैं।

पब्लिक प्लेस वाई फाई के इस्तेमाल से बचें

हम सभी लोग सार्वजनिक वाई-फाई का इस्तेमाल बड़े मजे में करते हैं। फोटो, वीडियो डाउनलोड करने के साथ-साथ पूरा फोन अपडेट कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह करना आपके फोन के लिए कितना खतरनाक है। इसलिए पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल होने वाले वाई-फाई का उपयोग करने से बचें। अगर आप किसी कारणवश इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट न करें।

मोबाइल को हमेशा सिक्योर मोड में रीस्टार्ट करें

फोन की स्पीड स्लो होने या फिर हैंग करने पर हम सभी लोग फोन को रीस्टार्ट कर उसकी परेशानी को सॉल्व (कॉल रिकॉर्डिंग) कर लेते हैं। लेकिन कई बार यह समस्या दूर नहीं होती है। ऐसे में आप जब कोई परेशानी समझ आती है तो आप अपने फोन बूट मोड में डाल दें। ऐसे करने से पर फोन सिक्योर मोड में चालू हो जाते हैं जिससे आप उस परेशानी के बारे में पता लगा सकते हैं जिसके कारण फोन में दिक्कत हो रही है।

समय से सॉफ्टवेयर अपडेट करें

अपने मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें। सॉफ्टवेयर को टाइम से अपडेट करने से फोन की सिक्योरिटी बढ़ती है और फोन के हैक होने की संभावना भी कम हो जाती है।

सुझाव

अगर आपके फोन में नियमित रूप से समस्या बनी हुई है तो ऐसे में आप इसे टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करें और अपने फोन को उनसे चेक कराएं।

कामकाजी महिलाओं को हमेशा रखना चाहिए इन बातों का ध्यान

शादी के बाद एक लड़की को अपने पति से ही नहीं बल्कि अपनी सास-ससुर से भी अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है। लेकिन तब क्या हो जब आप घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही हों।

वो जमाना गया जब महिलाएं घर की चार दीवारी में रहकर ही अपना पूरा जीवन काट देती थीं। आज की महिलाएं न केवल अपने अधिकारों को लेकर स्वतंत्र हैं बल्कि पुरुषों की तरह घर से बाहर निकल अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी कामयाब हो रही हैं। हां, वो बात अलग है कि लाख-पढ़ी लिखी होने के बाद भी लड़कियों को ससुराल जैसी पारंपरिक भूमिकाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें न केवल अपने पति के दिल में जगह बनानी होती है बल्कि अपने सास-ससुर संग एक अच्छे रिश्ते की शुरूआत करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी में से एक है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कामकाजी महिलाओं के साथ है, जिन्हें हर पल इस बात की चिंता सताती रहती है कि घर और ऑफिस के बीच क्या वह अपनी संतुलन भूमिकाएं निभा भी पाएंगी या नहीं?

खैर, हम इस तर्क-वितर्क से किसी नतीजे पर पहुंचें उससे पहले आपको बता दें कि जहां कुछ महिलाओं ने एक संयुक्त परिवार में रहने के कई दोष बताएं हैं तो वहीं इसके विपरीत कई कामकाजी महिलाओं का ऐसा कहना है कि एक संयुक्त परिवार में रहना आपके लिए एक मजबूत समर्थन बन सकता है बशर्ते आपको काम और घर के बीच बैलेंस बनाना आता हो। ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि कम समय में ही आप सभी की लाडली बन जाए तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखें।

काम के साथ घर को भी प्राथमिकता

हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि एक लड़की के लिए उसका करियर कितना महत्व रखता है लेकिन शादी के बाद आपको यह भी समझना चाहिए कि अब आप अकेले नहीं है आपका अपना एक परिवार है, जिसके हिसाब से भी अब आपको चीजों को मैनेज करना होगा। शादी से पहले जहां घंटों-घंटों आप ऑफिस में काम करती थीं तो वहीं अब आपको अपने परिवार के लिए भी समय निकालना होगा साथ ही साथ घर खर्च के हिसाब से लेकर पार्टनर के माता-पिता की देखरेख करने तक आपको कई बातों को भी ध्यान रखना होगा।

सुनें और समझें

अगर आप वाकई में चाहती हैं कि आप काम के साथ-साथ अपने परिवार की भी लाडली बनी रहीं तो सबसे पहले बातों को सुनने और समझने की आदत डालें। ऐसा करने से न केवल आप अपने सास-ससुर के मन की बातों को जान पाएंगी बल्कि वह भी आपके काम के महत्व को समझेंगे। यही नहीं, अपने परिवार के हर सदस्यों को जानने की कोशिश करें। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताएं कि घर की जिम्मेदारी को निभाने में आपके लिया क्या संभव है और क्या नहीं।

पति से हो खुलकर बात

किसी ने ठीक ही कहा है कि सबसे अच्छी शादी वह होती है जिसमें पति-पत्नी एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हों। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ प्यार करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। ऐसे में कोशिश करें कि आप और आपके पति के बीच एक स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता हो। इसके बाद आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुद फर्क समझ आ जाएगा।

फिल्मों के बजट का बड़ा हिस्सा स्टार्स पर खर्च होता है

पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' इस महीने रिलीज को तैयार है। इससे पहले हाल ही में उन्होंने भारतीय सिनेमा में बजट के मॉडल को लेकर बात की। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि पूरे बजट का एक बड़ा हिस्सा सितारे ले लेते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन के लिए कम बजट बचता है। यह मॉडल लंबे वक्त तक नहीं चलेगा।

गिप्पी ग्रेवाल ने बॉलीवुड की टूटी अर्थव्यवस्था और खराब बजट मॉडल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फिल्मों से 79 प्रतिशत हिस्सा एक्टर ले जाते हैं। उनका कहना है कि बजट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। गिप्पी ग्रेवाल ने कहा कि स्टार्स की बढ़ती फीस और घटता प्रोडक्शन बजट। इंडियन सिनेमा में बजट का एक ऐसा मॉडल बन गया है, जो लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसमें फिल्म के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन के बजाय टैलेंट (स्टार्स) पर खर्च हो जाता है।

विदेशी इंडस्ट्री से तुलना की

गिप्पी ग्रेवाल का कहना है, 'कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, कास्ट, डायरेक्टर और राइटर की कुल फीस फिल्म के बजट का लगभग 21 प्रतिशत होती है। बाकी 79 प्रतिशत हिस्सा फिल्म बनाने में खर्च होता है। यहां अक्सर इसका उल्टा होता है'। गिप्पी ग्रेवाल ने कहा, 'लगभग 79 प्रतिशत हिस्सा तो टीम ही ले जाती है, जिससे फिल्म बनाने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। कलाकार करोड़ों रुपये लेते हैं और यहीं से असंतुलन शुरू होता है'।

लागत पर ध्यान की बजाय सुधार की जरूरत

गिप्पी ग्रेवाल का मानना है कि सिर्फ लागत कम करने पर ध्यान देने के बजाय, इंडस्ट्री को सुधार की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, 'यह रिकवरी मॉडल है। अगर रिकवरी स्वस्थ हो जाती है, तो उत्पादन मूल्यों में काफी सुधार हो सकता है। दिन के आखिर में, यह सब गणित है'। स्टार्स की फीस पर लगी सीमा (कैपिंग) को लेकर हो रही बहस पर वे कहते हैं कि बार-बार बॉक्स-ऑफिस पर फ्लॉप होने के बावजूद मार्केट एक्टर्स को अच्छा पैसा देता रहता है।

रुक्मिणी वसंत के साथ फिल्म बनाने जा रहे नानी

लीड एक्टर की तलाश जारी

साउथ के अभिनेता और फिल्ममेकर नानी अपने प्रोडक्शन हाउस 'वॉल पोस्टर सिनेमा' के तहत एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर 'कांतारा चैप्टर 1' की अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत को कास्ट किया गया है। खबरों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को मुरलीकांत देवसोथ डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्ममेकर को पहले अपनी रूरल ड्रामा फिल्म 'धंडोरा' के लिए तारीफ मिल चुकी है।

स्क्रिप्ट और प्री-प्रोडक्शन का काम जारी

नानी की टीम अभी स्क्रिप्ट और प्री-प्रोडक्शन के दूसरे कामों पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि मुरलीकांत कहानी को फाइनल टच दे रहे हैं और साथ ही सपोर्टिंग कास्ट और टेक्निकल क्रू को भी तय कर रहे हैं। मेकर्स फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले हर पहलू की सावधानी से प्लानिंग कर रहे हैं।

लीड एक्ट्रेस का हुआ चुनाव

इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बड़ी अपडेट फीमेल लीड का चुनाव है। खबर है कि हीरोइन के रोल के लिए एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत को चुना गया है। एक्ट्रेस ने फिल्म का हिस्सा बनने के लिए हामी भर दी है। रुक्मिणी अपनी परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में रही हैं।

जारी है लीड एक्टर की तलाश

खबर है कि इस फिल्म के लिए लीड एक्टर की तलाश अभी जारी है। प्रोडक्शन टीम ऐसे सही एक्टर की तलाश में है जो कहानी में फिट बैठे और किरदार में जान डाल सके। हीरो के तय होने के बाद, मेकर्स के इस प्रोजेक्ट के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने की उम्मीद है।

कब शुरू हो सकती है शूटिंग?

फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होने की संभावना है। तब तक टीम तैयारी जारी रखेगी और जरूरी शुरुआती काम पूरे कर लेगी। चूंकि फिल्म नानी के बैनर तले बन रही है, इसलिए फिल्म प्रेमियों के बीच अभी से उम्मीदें बढ़ रही हैं।

अदा शर्मा ने मराठी सिनेमा की तरफ बढ़ाए कदम

'द केरल स्टोरी' और '1920' जैसी फिल्मों से दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाली अदा शर्मा अब मराठी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हैं। उनकी पहली फिल्म होगी 'गजरा'। इसका एलान हो गया है। साथ ही पहली झलक भी सामने आई है।

अदा शर्मा की डेब्यू मराठी फिल्म 'गजरा' का आधिकारिक एलान कर दिया गया है। यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी। अदा इसमें लीड रोल निभाती नजर आएंगी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर कर यह जानकारी साझा की है। साथ ही लिखा है, 'मराठी में मेरी पहली फिल्म 'गजरा'। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है'।

अदा ने फैंस से की ये गुजारिश

अदा शर्मा ने आगे लिखा है, 'मेरी पहली फिल्म '1920' से 'केरल स्टोरी', 'सनफ्लावर', 'कमांडो', 'बस्तर', 'रीता सान्याल' तक, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। हार्टअटैक, क्षणम, राणा विक्रम और मेरी सभी साउथ फिल्मों के लिए भी खूब प्यार दिया। मुझे अपने मराठी डेब्यू के लिए भी आप सभी के आशीर्वाद, साथ और प्यार की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सभी को गौरवान्वित कर सकूंगी और एक ऐसी फिल्म बना सकूंगी, जिसे आप सभी पसंद करें।

सच्ची घटना पर आधारित होगी कहानी

फिल्म का पोस्टर काफी दिलचस्प है। इससे सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक अंधेरे, परेशान करने वाली और कठिन कहानी का संकेत मिल रहा है। अदा शर्मा की इस फिल्म का निर्देशन श्रेयस जाधव कर रहे हैं। वहीं, फिल्म का निर्माण अमोल बोरकर कर रहे हैं। गणराज स्टूडियोज की पेशकश फिल्म 'गजरा' जिग जैग प्रोडक्शन्स की पहली फिल्म है। अदा ने अपने पोस्ट में यह बताया है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है।

देवदत्त मनीषा बाजी का होगा संगीत

फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी देवदत्त मनीषा बाजी संभालेंगे। बता दें कि देवदत्त महाराष्ट्र के एक जाने-माने संगीतकार, म्यूजिक अरेंजर और प्रोड्यूसर हैं। वे मराठी सिनेमा में अपने शानदार ऐतिहासिक और लोक-संगीत के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय हैं।

'द आर्चीज' नहीं मिलती तो नौकरी ढूंढ रहा होता, इस फिल्म ने बदली जिंदगी

अभिनेता वेदांग रैना इन दिनों अपनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी बीच अभिनेता ने अपनी डेब्यू फिल्म 'द आर्चीज' को लेकर खुलकर बात की। बातचीत में वेदांग रैना ने बताया कि 'द आर्चीज' उनके लिए सिर्फ पहली फिल्म नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला मौका थी। अभिनेता ने कहा, 'अगर 'द आर्चीज' मुझे नहीं मिलती, तो शायद मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही होती। उस समय मैं नौकरी ढूंढ रहा था और एमबीए के लिए आवेदन करने की तैयारी भी कर रहा था। मैं एक ऐसे मोड़ पर था, जहां मेरा भविष्य कुछ और ही हो सकता था।'

मैंने कभी उस पूरे अनुभव को बुरे नजरिए से नहीं देखा

फिल्म रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर हुई आलोचना और ट्रोलिंग को लेकर वेदांग ने कहा कि उन्होंने कभी भी इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो मैंने उस पूरे अनुभव को कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं पहली बार इतने बड़े स्तर पर स्क्रीन पर नजर आ रहा था और लोग मेरा काम देख रहे थे। मैं उस मौके के लिए बेहद खुश था।'

इस फिल्म ने मेरी जिंदगी बदल दी

वेदांग ने साफ कहा कि लोगों की राय अपनी जगह है। लेकिन उनके लिए यह फिल्म सपनों को सच करने वाला मौका साबित हुई। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए उस फिल्म का मतलब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इसलिए मैंने हमेशा उस अनुभव को अच्छे नजरिए से देखा। लोगों की राय अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे ऐसा मौका मिला, जिसने मेरे सपनों को सच कर दिया। आज भी मैं उस मौके के लिए बेहद शुक्रगुजार हूं।'

आज भी बाकी कलाकारों के संपर्क में हैं वेदांग

वेदांग रैना ने यह भी बताया कि 'द आर्चीज' की पूरी स्टारकास्ट आज भी एक-दूसरे के संपर्क में रहती है। हालांकि सभी अपने-अपने काम में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा, 'हम टच में हैं। सब लोग बहुत बिजी हो जाते हैं। जब मैं शूट कर रहा होता हूं तो बाकी लोग अपने काम में लगे होते हैं। सबकी अपनी-अपनी जर्नी है, लेकिन हम एक-दूसरे को मैसेज करते रहते हैं। किसी की फिल्म आती है तो उसे बधाई भी देते हैं।' बता दें कि 'द आर्चीज' 7 दिसंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर ने किया था। इस फिल्म से सुहाना खान, अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, वेदांग रैना, मिहिर आहूजा, अदिति सहगल और युवराज मेंडा ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था।

मां बनने के बाद बहुत सारा काम हाथ से गया

डर और इन्सिक्योरिटी दोनों सताते हैं

रुबीना दिलैक ने बताया कि मां बनने के बाद जिंदगी कैसे बदल गई है। उन्होंने कहा कि जीवा और ईधा जुड़वा बेटियों के पालन -पोषण में उन्हें पति अभिनव का पूरा साथ मिला है। उन्होंने बताया- मुझसे तो कई लोगों ने कहा भी कि मां बन जाओगी, तो में लीड रोल नहीं मिलेंगे।

टेलिविजन जगत की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक को इंडस्ट्री में लंबा अरसा हो गया है, मगर बीते वक्त के साथ वे निखरती चली गई हैं। फिक्शन शोज हों या नॉन फिक्शन अथवा हों रियलिटी शोज, वे हर जगह चमकी हैं। दो जुड़वा बेटियों की मां रुबीना फैशन गोल्स ही नहीं बल्कि फैमिली गोल्स भी सेट करती नजर आती हैं। उनका मानना है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण जरूर है, मगर असंभव नहीं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कभी बिकीनी तो कभी अपने सेक्सी कॉस्टयूम से रुबीना चर्चा में रहती हैं। खुद को कैसे मेंटेन कर पाती हैं? इस सवाल के जवाब में वे कहती हैं, 'आपको अपने दिमाग और बॉडी को एक खास तरह की फिटनेस के साथ रखना ही पड़ता है, फिर इसके बाद खूबसूरत लगना बायप्रोडक्ट हो जाता है। मैं किसी खास शेप या फिगर के लिए ऐसा नहीं करती। मुझे अपनी एनर्जी हाइ चाहिए और मेरी परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी वजह से मैं हेल्दी रहना पसंद करती हूं। इसके लिए मैं डिसिप्लिन में रहना पसंद करती हूं।'

शादी में लगा था बहुत हो गया, अब बस

रुबीना और उनके पति अभिनव शुक्ला की शादी कई उतार-चढ़ाव से गुजरी। बिग बॉस 14 में जाने से पहले उनकी शादी तलाक के कगार तक पहुंच गई थी। रुबीना कहती हैं, 'हम अपनी शादी में ये जान चुके हैं कि बॉलिवुड से हमें आइडिया ऑफ लव बेचा गया है। मगर असलियत में वो वैसा नहीं है। प्यार हर रोज का कमिटमेंट है। जब आप सुबह उठते हैं और अपने पार्टनर की आंखों में देखते हैं, तो उनकी तमाम बुराइयों, कमियों और नकारत्मकता के बावजूद आप उनके साथ रहना चाहते हैं, तो वही प्यार है। आपको लगातार रिश्तों पर काम करना पड़ता है। मगर यदि आप ये सोचते हैं कि ये मैं इसके साथ कहां फंस गई, तो फिर उस रिलेशनशिप से तुरंत निकल जाइए। हमारी शादी में अभिनव ने मेरे मामले में कभी हार नहीं मानी। हां मैं कह देती थी, आइ एम डन, बहुत हो गयाा, अब नहीं।' तब अभिनव कहते, 'शांत हो जाओ, थोड़ा सोच लो' अभिनव ने मुझे बहुत संभाला।' सभी जानते हैं कि रुबीना जीवा और ईधा जैसी दो जुड़वा बेटियों की मां हैं, मगर ट्विंस के पालन - पोषण में उन्हें पति अभिनव का पूरा साथ मिला है। वे कहती हैं, 'बच्चों के पालन-पोषण में बहुत पेरेंट्स की पार्टनशिप बहुत जरूरी है और हम उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं।'

वो कहते, मां बनने के बाद लीड रोल नहीं मिलेंगे

कई बार मदरहुड महिलाओं के लिए रुकावट भी बन जाता है। मगर क्या एंटरटेनमेंट की दुनिया में भीअभिनेत्रियों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है? इस पर रुबीना कहती हैं, 'मैं आपको बताना चाहूंगी कि 60 से 65 प्रतिशत महिलाएं मां बनने के बाद काम रेज्यूम नहीं कर पातीं, क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। हमने ऐसा कोई इकोसिस्टम भी नहीं बनाया, जहां नई मांएं अपने मदरहुड के साथ करियर भी आगे बढ़ा सकें। हमारी इंडस्ट्री की खासियत ये हैं कि हम काम पर रेज्यूम करना चुन सकते हैं। मगर हमारे काम करने का नेचर ऐसा बन गया है कि लोग आपको लेबल और जज करना शुरू कर देते हैं। जैसे 'मां बन गई है, उम्र दिखने लगी है', 'अलग सी दिखने लगी है', 'अब ये वाले रोल नहीं भाते' तो अब यहां आपको एक बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जी वाले माइंडसेट के साथ काम करना है, तो साथ में सुंदर भी लगना है, तो एक अलग तरह का दबाव रहता है। मुझसे तो कई लोगों ने कहा भी कि मां बन जाओगी, तो में लीड रोल नहीं मिलेंगे। डर और इन्सिक्योरिटी दोनों सताते है, मगर आपको उसी के बीच रास्ता तलाशना होता है। मां बनने के बाद मेरे हाथ से बहुत सारा काम और प्रॉजेक्ट्स गए हैं।'

प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 की स्थायी सूची का ग्राम सभा में हुआ सत्यापन

जिला के सभी 471 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ ग्राम सभा में लिया भाग, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विकसित भारत जी राम जी योजना पर ग्रामीणों को दी गई जानकारी

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कबीरधाम जिले के सभी 471 ग्राम पंचायतों और उनके आश्रित ग्रामो में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 के स्थाई सूची का वाचन किया गया। सूची में दर्ज ग्रामीणों का सम्पूर्ण विवरण ग्राम सभा में वाचन करते हुए नाम, आयु, लिंग जैसी जानकारी का सत्यापन कर आवश्यकता अनुसार त्रुटि सुधार किया गया। ग्राम सभा के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने सम्पूर्ण प्रक्रिया को देखते हुए योजना अंतर्गत स्थाई सूची की पूरी जानकारी ली।

इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के स्थान पर 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। ग्राम सभा मे विकसित भारत जी राम जी योजना से ग्रामीणों को मिलने वाले 125 दिनों के रोजगार, सात दिवस में मजदूरी भुगतान, काम की मांग पर रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, आजीविका, जल संरक्षण के साथ महिलाएं एवं युवाओं को मिलने वाले फायदे के बारे में बताया गया। साथ ही वर्तमान मजदूरी दर बेरोजगारी भत्ता पारदशिर्ता एवं जवाबदेही जैसे प्रमुख बदलाव के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई। नए योजना में कार्य की चार प्रमुख श्रेणियां जिसमें जल सुरक्षा और संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात की गई।

प्रधानमंत्री अवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल हितग्राहियों के नाम का वाचन ग्राम सभा मे किया गया। उल्लेखनीय है कि जिले में सर्वेक्षित हितग्राहियों का नाम सूची में दर्ज है। जिसमें जनपद पंचायत बोड़ला, कवर्धा, पंडरिया एवं स.लोहारा के हजारो ग्रामीण हितग्राही परिवार शामिल है। विशेष ग्राम सभा में पूरी सूची का वाचन और पात्रता का परीक्षण किया गया। प्राप्त आपत्तियों पर जांच परीक्षण उपरांत निराकरण करते हुए हितग्राहियों की अंतिम सूची तैयार किया गया।पारदशिर्ता रूप से सूची को आम जनता के समक्ष ग्राम सभा के पटल पर रखा गया। साथ ही योग्य लाभार्थियों को प्राथमिकता देने हेतु चर्चा की गई। अंतिम सूची को अनुमोदन के पश्चात आवास प्लस 2.0 के पोर्टल में अपलोड किया जाएगा जिससे पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभांवित किया जा सके।

खास खबर

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से खेती को मिली नई दिशा, किसान लखेश्वर बने आत्मनिर्भर

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

विकासखंड खैरागढ़ के ग्राम मंडला निवासी किसान श्री लखेश्वर देसलहरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होकर अपनी कृषि गतिविधियों को और बेहतर ढंग से संचालित कर रहे हैं। उन्हें योजना की सभी किस्तों के साथ हाल ही में जारी 23वीं किस्त की राशि भी प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग उन्होंने खेती-किसानी के कार्यों में किया। श्री देसलहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए खेती के समय काफी उपयोगी साबित होती है। योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग वे बीज, खाद, कीटनाशक तथा अन्य कृषि आदानों की खरीद में करते हैं, जिससे खेती की लागत कम करने और समय पर कृषि कार्य संपादित करने में सहायता मिलती है।

उन्होंने कहा कि पहले कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब योजना से मिलने वाली नियमित सहायता के कारण खेती की तैयारियां समय पर हो जाती हैं। इससे फसल उत्पादन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। किसान लखेश्वर देसलहरा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना छोटे और मध्यम किसानों के लिए संबल का कार्य कर रही है। योजना से प्राप्त राशि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बेरला क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा। जिले के बेरला क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की सक्रिय कार्रवाई के तहत विभिन्न गांवों में दबिश देकर अवैध शराब की जब्ती, आरोपियों की गिरफ्तारी तथा प्रकरण दर्ज करने जैसी प्रभावी कार्रवाई की गई है। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कलेक्टर को भेजी गई प्रतिवेदन के अनुसार, समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देशानुसार तत्काल जांच कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

कार्रवाई के दौरान ग्राम टकसिवा निवासी सुमित्रा सोनवानी पति राजेंद्र सोनवानी के रिहायशी परिसर से अवैध रूप से विक्रय हेतु रखी गई देशी मसाला शराब जब्त की गई। वहीं ग्राम कोदवा निवासी कुशाल बारले पिता तारण बारले के कब्जे से भी अवैध देशी मदिरा बरामद की गई। दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा ग्राम रांका सहित अन्य संदिग्ध स्थानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग द्वारा लगातार निगरानी एवं सूचना संकलन के माध्यम से अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। आबकारी विभाग ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक वृत्त-बेरला क्षेत्र में अवैध मदिरा से संबंधित 24 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इन कार्रवाईयों के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक वाहन भी जब्त किया गया है। विभाग द्वारा नियमित गश्त, छापामार कार्रवाई एवं जनसूचनाओं के आधार पर अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की लगातार सक्रियता से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

एक जुलाई से लागू होगी वीबी जी राम जी योजना बेमेतरा जिला में जनजागरण अभियान बना मिसाल

कलेक्टर के निर्देशन में ग्राम पंचायत सांकरा व देवरी में मानव श्रृंखला बनाकर ग्रामीणों ने दिया जनभागीदारी का संदेश

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन एवं समग्र विकास को नई दिशा देने वाली वीबी जी राम जी (विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण) योजना आगामी 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक जन-जागरूकता के लिए बेमेतरा जिले में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशन में जिले के सभी विकासखंडों में प्रशिक्षण, जनसंपर्क, ग्राम सभाएं, चौपाल, रैली एवं जनजागरूकता गतिविधियों को गति दी गई है।

योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला स्तर पर लगातार बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों, लाभों, पात्रता एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

सांकरा एवं देवरी में मानव श्रृंखला बनी आकर्षण का केंद्र

जनपद पंचायत बेरला अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा एवं देवरी में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं तथा युवाओं ने योजना के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाकर जनभागीदारी का अनूठा संदेश दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण हाथों में तख्तियां एवं जागरूकता संदेश लेकर शामिल हुए। इस दौरान वीबी जी राम जी गांव की प्रगति, हम सबकी जिम्मेदारी, सशक्त गांव, समृद्ध परिवार, रोजगार और आजीविका का नया संबल तथा जनभागीदारी से होगा विकास जैसे नारों के माध्यम से लोगों को योजना से जुड़ने और उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

मानव श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीणों ने यह संदेश दिया कि यह योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भागीदारी का एक व्यापक अभियान है। ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि गांव के प्रत्येक पात्र परिवार तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाएगी तथा उन्हें लाभ दिलाने में सक्रिय सहयोग किया जाएगा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सराहना

बेमेतरा जिले में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की गूंज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बेमेतरा की मानव श्रृंखला की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से आई यह तस्वीर ग्रामीण जनजागरूकता, सहभागिता और आत्मविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच के माध्यम से बेमेतरा जिले के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे योजना के प्रति जनजागरूकता और जन सहभागिता का प्रेरणादायी मॉडल बताया है।

ग्राम सभाओं के माध्यम से पहुंचाई जा रही योजना की जानकारी

जिले के गांव-गांव में आयोजित ग्राम सभाओं एवं जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को रोजगार एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर परिवारों की आय में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के सफल संचालन के लिए पंचायत स्तर पर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, जिससे योजना लागू होने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ मिल सके।

30 जून तक पूर्ण होगा व्यापक प्रशिक्षण अभियान

जिला प्रशासन द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों, युवाओं एवं हितग्राहियों को योजना की कार्यप्रणाली, पात्रता, लाभ एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रशासन ने 30 जून 2026 तक सभी संबंधित हितधारकों का प्रशिक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि 1 जुलाई से योजना का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सके।

प्रचार-प्रसार के लिए अपनाए जा रहे बहुआयामी माध्यम

योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, जागरूकता रैलियों, पोस्टर-बैनर, मुनादी, रथ प्रचार, जनसंवाद कार्यक्रमों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। सरपंच, पंच, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन भी अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने भी किया संवाद

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी मंगलवार को अपने फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आगामी ग्राम सभाओं एवं वीबी जी राम जी योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हुए लोगों के प्रश्नों का समाधान किया तथा योजना को ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

साकार होगा विकसित और आत्मनिर्भर गांव का संकल्प

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता जनभागीदारी से ही सुनिश्चित होती है। उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाए तथा उन्हें समय पर योजना से जोड़ा जाए। बेमेतरा जिले में चलाया जा रहा यह जागरूकता अभियान न केवल योजना के सफल क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों में विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता, सहभागिता एवं स्वामित्व की भावना को भी सशक्त बना रहा है। सांकरा और देवरी में बनी मानव श्रृंखला इस बात का प्रतीक है कि ग्रामीण समाज विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

जल जीवन मिशन के कार्यों में लाएं गति, हर घर तक पहुंचे स्वच्छ पेयजल : जिला पंचायत सीईओ

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशन में आज जिला पंचायत सीईओ सुश्री प्रेमलता पद्माकर द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित कर जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मिशन के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, लंबित भुगतान, जल गुणवत्ता परीक्षण, अधोसंरचना विकास तथा स्वच्छता गतिविधियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में एसएनए स्पर्श के अंतर्गत लंबित देयकों के भुगतान तथा 1 अप्रैल 2026 के पश्चात प्राप्त आवंटन एवं किए गए भुगतानों के अनुमोदन संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीईओ जिला पंचायत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भुगतान संबंधी सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो और योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से जारी रहे।

बैठक में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा प्रदत्त कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन एंड रिफॉर्म प्लान के क्रियान्वयन एवं अनुमोदन पर चर्चा की गई। इस दौरान योजना के विभिन्न घटकों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित काययीजना के अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा पर बल दिया गया।

बैठक में एनएबीएल लैब हेतु आवश्यक रसायन एवं उपकरणों की जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मिशन का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए जल गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए। उन्होंने प्रयोगशालाओं में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नियमित रूप से जल नमूनों की जांच करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिले में संचालित जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए पाइपलाइन विस्तार, घरेलू नल कनेक्शन, जल स्रोतों के विकास तथा जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया जाए तथा निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर के निर्देश पर अवैध खाद भंडारण पर कृषि विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 313 बोरी उर्वरक जब्त

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशन एवं उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी के मार्गदर्शन में खरीफ मौसम 2026 के मद्देनजर उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा जिले में खाद, बीज विक्रय केंद्रों तथा संभावित अवैध भंडारण स्थलों का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि विभाग ने अवैध खाद भंडारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 313 बोरी उर्वरक जब्त किए हैं।

विकासखंड छुईखदान के ग्राम अचानकपुर (पैलीमेटा) में व्यवसायी अनिल साहू के गोदाम का निरीक्षण करने पर बिना वैध दस्तावेजों के 94 बोरी उर्वरक का भंडारण पाया गया। प्रारंभिक जांच में यह भंडारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संपूर्ण स्टॉक जब्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।

इसी प्रकार विकासखंड खैरागढ़ के ग्राम गाडाघाट स्थित साहू किराना स्टोर में बिना अनुज्ञप्ति के यूरिया विक्रय किए जाने की सूचना पर संबंधित प्रोपराइटर नानक दास साहू के गर्रापार स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में बिना वैध दस्तावेजों के 58 बोरी डीएपी तथा 72 बोरी यूरिया सहित कुल 219 बोरी उर्वरक का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर व्यवसायी द्वारा बिल एवं उर्वरक खरीदी संबंधी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद गोदाम में उपलब्ध समस्त उर्वरकों को जब्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद, बीज एवं कीटनाशक खरीदें तथा खरीदारी का पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। विभाग ने कहा है कि कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, अवैध भंडारण अथवा नकली खाद से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल अधिकारियों को दें, ताकि समय पर कार्रवाई कर किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

केसीजी जिले के गंडई क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर संयुक्त कार्रवाई

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत गंडई-पंडरिया क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 10 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2,200 का अथर्दंड वसूल किया गया। कार्रवाई के दौरान तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त प्रवर्तन दल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनम फातिमा, औषधि निरीक्षक नवीन बघेल, पुलिस विभाग से उप निरीक्षक चंद्रशेखर साहू एवं प्रधान आरक्षक सियाराम ध्रुव शामिल रहे। इस कार्रवाई में विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णत: निषिद्ध है। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थानों एवं छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित होने संबंधी जानकारी भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू अथवा अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

अवैध मुरूम उत्खनन करते दो वाहन जब्त

कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने 23 जून को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान शिकायतित क्षेत्र में बजरी के अवैध उत्खनन अथवा परिवहन में संलग्न कोई वाहन नहीं पाया गया। खनिज अमले द्वारा आसपास के क्षेत्रों में भी जांच की गई। इस दौरान ग्राम नादिया स्थित सुरही नदी के पास मुरूम एवं मिट्टी का अवैध उत्खनन करते हुए दो वाहन पाए गए। मौके पर संबंधित व्यक्तियों से उत्खनन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कार्रवाई की गई। खनिज विभाग ने उत्खनन कार्य में संलग्न जेसीबी मशीन क्रमांक सीजी 08 एडब्ल्यू 2801 तथा हाइवा क्रमांक सीजी 08 एजे 9088 को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से थाना गंडई में रखा है। जांच में पाया गया कि जेसीबी का संचालन कमलेश्वर निवासी पथर्रा द्वारा किया जा रहा था, जबकि वाहन स्वामी तहसील पटेल निवासी नादिया हैं। वहीं हाइवा वाहन चालक धनीराम निवासी निवासपुर तथा वाहन स्वामी मिथलेश साहू निवासी देवपुरा बताए गए हैं। खनिज विभाग के अनुसार प्रकरण में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज जांच दल द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा ऐसे मामलों में नियमित कार्रवाई जारी है।

स्कूलों में मंत्र अनिवार्य करने का आदेश निरस्त करने की मांग, आदिवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन

15 सूत्रीय मांगों में संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

गोंडवाना यूथ क्लब, सर्व आदिवासी समाज और भीम आर्मी के संयुक्त बैनर तले आदिवासी समाज ने मंगलवार को कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 15 सूत्रीय मांगों के साथ स्कूलों में मंत्रों को अनिवार्य करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई।

मंत्र थोपना न्यायसंगत नहीं

सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक ललित कुमरे ने कहा कि आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष जसवंत गावड़े ने कहा कि शासकीय विद्यालयों में प्रार्थना के दौरान मंत्र और धार्मिक गतिविधियों को अनिवार्य करना उचित नहीं है।

संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ

ज्ञापन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ बहुधार्मिक प्रदेश है। यहां आदिवासी समुदायों की अपनी अलग धार्मिक मान्यताएं, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान है। राज्य संचालित स्कूलों में किसी विशेष धार्मिक परंपरा के मंत्र अनिवार्य करना संविधान की धर्मनिरपेक्ष मान्यता और सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ है।

15 सूत्रीय मांगों में ये प्रमुख

1. स्थानीय को प्राथमिकताः अनुसूचित क्षेत्रों की सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
2. फर्जी जाति प्रमाण पत्रः मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, छह महीने में निराकरण हो।
3. निजीकरण पर रोकः अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खनिज, वन सेवाओं का निजीकरण रोका जाए।
4. जमीन लीज का प्रावधान खत्म होः भू-राजस्व संहिता के तहत आदिवासी जमीन लीज पर देने का प्रावधान समाप्त किया जाए।
5. खनिज में हिस्सेदारीः खनिज संपदा से लाभ में ग्रामसभा और आदिवासी समुदायों की प्रत्यक्ष भागीदारी तय हो।
6. नक्सल मामलों की समीक्षाः जेलों में बंद निदोष आदिवासी युवाओं के मामलों की उच्च स्तरीय जांच कर रिहाई हो।
7. यूसीसी से बाहरः समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को अलग रखा जाए।
8. पेसा कानून का पालनः पेसा अधिनियम के सभी प्रावधान जमीनी स्तर पर लागू किए जाएं।

समाज ने आगामी जनगणना में आदिवासियों की सही जनसंख्या और सामाजिक स्थिति दर्ज करने की मांग भी की है।

नलकूप खनन पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ाया

बेमेतरा। जिले में भूजल स्तर के संरक्षण एवं पेयजल स्रोतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने नलकूप (बोरवेल) खनन पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि को आगामी 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। मानसून के आगमन में हो रही देरी तथा संभावित जल संकट की स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बेमेतरा के पूर्व आदेश 31 दिसंबर 2025 के तहत जिले को पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 (क्रमांक-3) एवं नियम 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 अथवा मानसून आगमन तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था तथा इस अवधि में नए नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्तमान में जिले में मानसून की सक्रियता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचने तथा भूजल स्तर पर संभावित प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने प्रतिबंध अवधि को पुनः 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 अथवा भूजल स्थिति की पुनसर्मीक्षा तक प्रभावशील रखने का निर्णय लिया है।

'भिलाई को उजड़ने से बचाएं' : लैंड मोनेटाइजेशन में निवासियों को पहला हक देने पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने की मांग

कुरैशी ने नीति आयोग को लिखा पत्र, कहा : BSP कर्मियों को कलेक्टर गाइडलाइन पर मिले आवास

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

केंद्र की लैंड मोनेटाइजेशन नीति को लेकर भिलाई में हलचल तेज हो गई है। पूर्व राज्य मंत्री और बीएसपी के भूतपूर्व कर्मचारी बदरुद्दीन कुरैशी ने नीति आयोग से मांग की है कि भिलाई टाउनशिप के आवासों पर पहला हक यहां के निवासियों और बीएसपी कर्मियों का हो।

नीति आयोग को भेजा मांग पत्र

कुरैशी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम को विस्तृत मांग पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि यदि टाउनशिप की जमीनों का मौद्रिकरण करना ही है तो फर्स्ट स्टेक होल्डर्स क्लेम यहां रह रहे पूर्व और वतर्मान कमर्चारियों का होना चाहिए।

'अब प्रबंधन के हाथ में कुछ नहीं'

पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्तियों की नीतियां अब सीधे नीति आयोग से तय हो रही हैं। पहले बीएसपी प्रबंधन लीज, लाइसेंस या रिटेंशन जैसी योजनाओं से कमर्चारियों को राहत देता था। अब स्थानीय प्रबंधन और जनप्रतिनिधि भी असहाय हैं।

जनप्रतिनिधियों से एकजुट होने की अपील

उन्होंने सांसद और सभी दलों के जनप्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की। कहा : "जो टाउनशिप से सचमुच करते हैं प्यार, वह ऐसी किसी भी योजना को नहीं करेंगे स्वीकार।" नीति आयोग से 'कर्मचारी प्रथम' नीति के तहत गाइडलाइन में संशोधन का आग्रह किया गया है ताकि भिलाई के लाखों परिवारों के आशियाने सुरक्षित रहें। सहित कुल चार वाहनों को जब्त किया।

NBCC बेचेगी टाउनशिप की जमीन

नीति आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक 220 सीपीएसई के पास रक्षा और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। प्लांट विस्तार के लिए जरूरी जमीन छोड़कर बाकी टाउनशिप की पूरी भूमि एनबीसीसी के जरिए बेची जाएगी। बीएसपी सिर्फ प्लांट चलाएगी। अस्पताल, टाउनशिप, स्कूल और मैत्री बाग जैसी संपत्तियां उसके पास नहीं रहेंगी। एमटीएनएल और डिफेंस की जमीनों पर यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

'कलेक्टर गाइडलाइन पर दें मालिकाना हक'

कुरैशी ने कहा कि भिलाई को उजड़ने से बचाने का एकमात्र विकल्प है कि क्वार्टर में रह रहे कमर्चारियों को प्लॉट साइज के अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन या मार्केट वैल्यू पर जमीन बेच दी जाए। बाकी खाली जमीन का मौद्रिकरण किया जा सकता है।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100